वर्ष: 9, अंक: 5-6,
अगस्त-सितंबर 2016, संयुक्तांक
मूल्य: एक प्रति 15 रुपये

कृषि चौपाल

कृषि मूलम् जगत् सर्वम्

कृषि एवं ग्रामीण विकास को समर्पित हिंदी मासिक

हरियाणा को नंबर-1 बनाना है

ओमप्रकाश धनखड़

बाढ़ से बेहाल जीवन

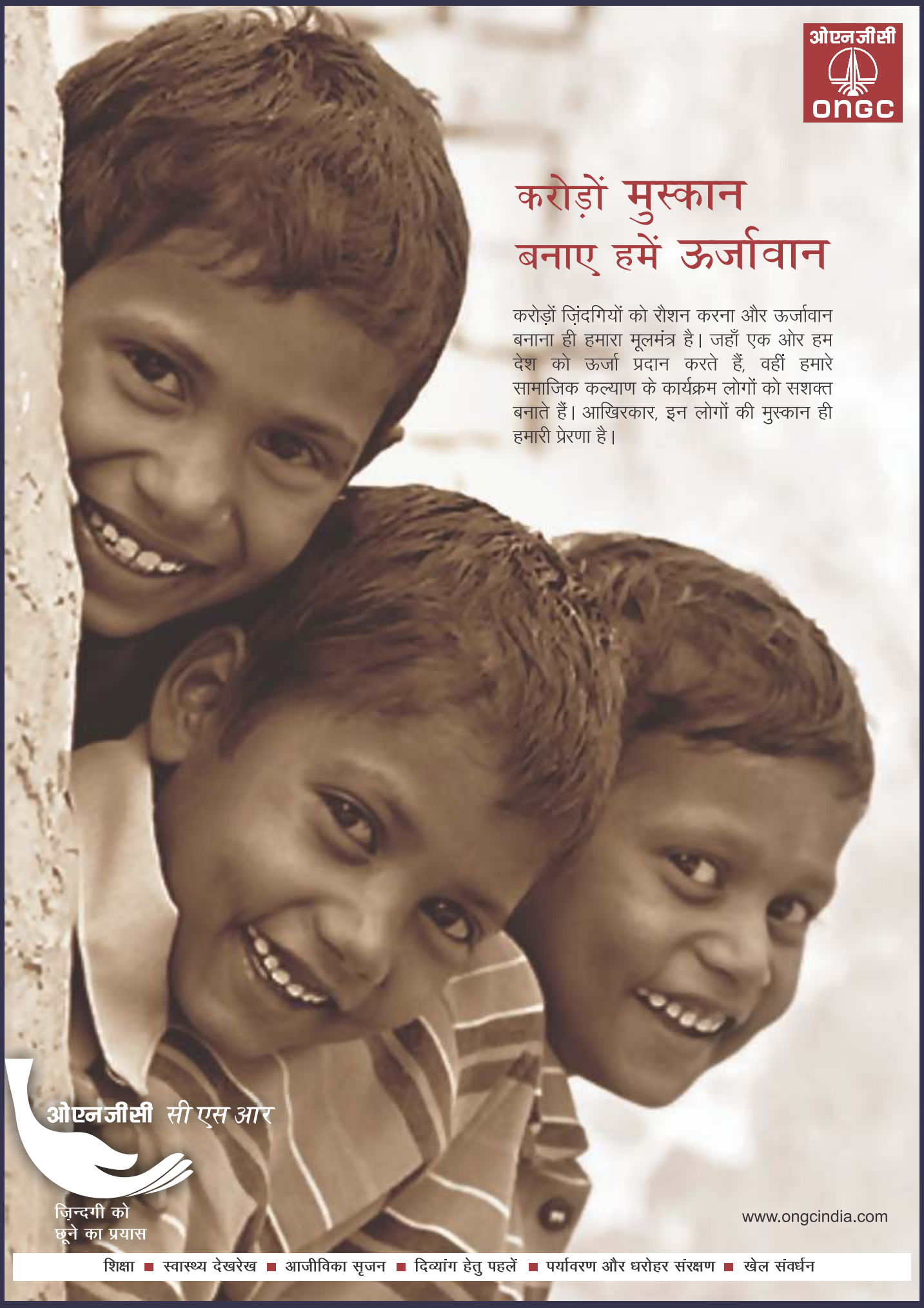

ओएनजीसी
ONGC
करोड़ों मुस्कान
बनाए हमें ऊर्जावान
करोड़ों ज़िंदगियों को रौशन करना और ऊर्जावान बनाना ही हमारा मूलमंत्र है। जहाँ एक ओर हम देश को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वहीं हमारे सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम लोगों को सशक्त बनाते हैं। आखिरकार, इन लोगों की मुस्कान ही हमारी प्रेरणा है।
ओएनजीसी सी एस आर
ज़िन्दगी को छूने का प्रयास
www.ongcindia.com
शिक्षा ■ स्वास्थ्य देखरेख ■ आजीविका सृजन ■ दिव्यांग हेतु पहलें ■ पर्यावरण और धरोहर संरक्षण ■ खेल संवर्धन

कृषि मूलम् जगत् सर्वम्

कृषि चौपाल

कृषि एवं ग्रामीण विकास को समर्पित हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्षः 9 ❖ अंकः 5-6 ❖ अगस्त-सितंबर 2016

संपादक
महेन्द्र सिंह बोरा

संपादक मंडल
डॉ. गंगाशरण सैनी, एस. विश्वजीत प्रसाद, प्रेम सुंदरियाल, डॉ. नवीन नैनवाल, महेश पपने

सहयोगी संपादक
ताज रावत

राजनीतिक संपादक
ललित पांडे

सहायक संपादक
खुशाल सिंह

ब्यूरो प्रमुख अल्मोड़ा
पुष्कर बिष्ट

प्रसार
दलीप जीना

डिजाइन
कल्पना प्रिंटोग्राफिक्स

संपादकीय कार्यालय
सी-355, तृतीय तल, गली नं. 9, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092

क्षेत्रीय कार्यालय
मानपुर वेस्ट, रामपुर रोड हल्लानी, जिला-नैनीताल, उत्तराखंड-263639

संपर्कः +91-9910406059, 8130956778, 7065857319

Email: krishichaupal@gmail.com
Website: krishichaupal.org

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक महेन्द्र सिंह बोरा लारा सी-355, तृतीय तल, गली नं. 9, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092 से प्रकाशित और मयंक ऑफसेट प्रोसेस, 794/95 गुरु रामदास नगर एक्सटेंशन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 से मुद्रित।

कृषि चौपाल पत्रिका से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा दिल्ली की सीमा में आने वाले सक्षम न्यायालयों में ही किया जाएगा।

● उपरोक्त सभी पद अवैतनिक हैं।

कवर फोटो साभारः darkroom.baltimoresun.com

तख्ते पर बैठे राहुल को किसान दिलाएंगे तख्त?

अभी कुछ समय पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ मुस्लिम नेता ने कहा कि यदि आप इंटरनेट पर नरेंद्र मोदी का मतलब खोजेंगे तो आपको बेवकूफ शब्द मिलेगा। शायद, इन नेताजी ने तब इंटरनेट पर राहुल गांधी खोजने की जहमत नहीं उठाई होगी वरना उन्हें खूब चुटकुले पढ़ने को मिलते। खैर, यह बात अब पुरानी हो गई है, क्योंकि इन दिनों इंटरनेट पर राहुल गांधी खोजने पर चुटकुले नहीं, बल्कि राहुल की किसान यात्रा का विवरण मिलता है। सात सितंबर से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में किसान यात्रा कर रहे हैं। 2500 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान राहुल, किसानों से रूबरू होकर उनका दुख-दर्द साझा कर रहे हैं। इस लिहाज से राहुल की यात्रा का विश्लेषण करें तो यह उनका बेहद सार्थक प्रयास माना जाएगा, लेकिन यात्रा के समय को लेकर यह शंका हो जाती है कि क्या वास्तव में वे किसानों के हितैषी हैं या फिर महज चुनाव जीतने के लिए यह सारी कवायद कर रहे हैं?

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और करीब तीन दशकों से यहां कांग्रेस मूर्छित पड़ी हुई है, इसलिए राहुल गांधी की यात्रा का मुख्य मकसद क्या है- क्या वे कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए गांव-गांव की खाक छान रहे हैं या फिर वे वास्तव में किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं? यहां यह समझने में मुश्किल नहीं होगी कि तख्ते पर बैठे राहुल गांधी का मुख्य मकसद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को तख्त दिलाना है और इसके लिए वे महज दिखाने के लिए किसानों के आंसू पोछ रहे हैं।

राहुल अपनी यात्रा के दौरान किसानों से खाट पर चर्चा कर रहे हैं। असल में, इसके पीछे राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का दिमाग काम कर रहा है। ये वही प्रशांत कुमार हैं, जो इससे पहले भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए चाय पर चर्चा, बिहार में जदयू नेता नीतीश कुमार के लिए हर घर दस्तक और पंजाब में कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए कॉफी पर चर्चा जैसे कार्यक्रम बना चुके हैं। प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को कांग्रेस का चेहरा बनाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेसी रणनीतिकारों को लगा कि इससे राहुल बाबा की छवि कमजोर पड़ जाएगी, इसलिए अंत में राहुल गांधी को मोर्चा संभालना पड़ा। जाहिर तौर पर राहुल का पूरा फोकस चुनाव जीतने पर होगा, ताकि भविष्य में वे सर्वमान्य तरीके से कांग्रेस का चेहरा बन पाएं। ऐसे में किसानों, दलितों, मुसलमानों इत्यादि को साधना उनकी मजबूरी बन चुकी है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वास्तव में राहुल को किसानों की चिंता नहीं, बल्कि वे किसानों की समस्याओं का मात्र जिक्र करके सत्ता पाना चाहते हैं। यह बात कड़वी है, लेकिन सच है कि जो राहुल अपनी पार्टी के नेताओं तक को मिलने का समय नहीं देते, वे यूं ही अपने घर से निकलकर किसानों का हालचाल जानने पहुंच जाएंगे। विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए उन्हें किसानों की याद आ रही है, ताकि उनका वोट बैंक मजबूत हो सके। अपनी यात्रा के दौरान राहुल उत्तर प्रदेश के किसानों के मसलों से ज्यादा बढ़ती महंगाई और विदेशी बैंकों में रखे काले धन को उठा रहे हैं। उनके निशाने पर किसानों का बकाया ऋण न चुकाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जाहिर तौर पर इसके पीछे उनका लक्ष्य क्या है, यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। किसान यात्रा के दौरान कांग्रेसी उनमें चौधरी चरण सिंह का अक्स देखने लगे हैं, लेकिन अभी उनकी तुलना चौधरी साहब से करना बेमानी होगा।

खैर, यह खबर भी आम हो चुकी है कि राहुल की यात्रा के दौरान जितने किसान उनसे मिल रहे हैं, उनमें से ज्यादातर पहले से कांग्रेसी हैं या फिर राहुल की बैठकें पूर्व प्रायोजित हैं, लेकिन प्रदेश का आम किसान राहुल की इस यात्रा के बारे में क्या राय रखता है, यह चुनावी नतीजों से ही पता चल पाएगा।

महेन्द्र सिंह बोरा
संपादक

इस अंक में...

कृषि समाचार	04
अर्थव्यवस्था में तेजी तो कृषि सुधारों से आएगी	12
खुश रहेगी गाय तो दूध होगा ज्यादा पौष्टिक	13
दलहन वर्ष में थाली से गायब दाल	14
हरित क्रांति के पुरोधा डॉ. स्वामीनाथन	15
हरियाणा को दूध उत्पादन में नंबर-1 बनाना है- ओमप्रकाश धनखड़	16
किसानों के रडार पर मोदी सरकार	18
सरकार किसानों की आय दोगुना करने की सोच रही है	19
बाढ़ से बेहाल जीवन	20
खाद्य तेल के लिए तोरिया उत्पादन	22
प्लास्टिक लो टनल तकनीक	25
कपास की फसल पर सफेद मक्खी का कहर	26
उत्तर पूर्वी राज्यों में जैविक खेती को प्रोत्साहन	27
गुलाब की व्यावसायिक खेती	28
उद्योग जगत के समाचार	30
राजनीतिः डॉ. निशंक से साक्षात्कार	32
किसान साहित्य	34

मध्य प्रदेश का हर तीसरा अफसर है किसान

मध्य प्रदेश का हर तीसरा आईएएस अफसर किसान है, लेकिन ज्यादातर के लिए खेती लाभ का धंधा नहीं है। कुछ अफसरों की खेती से आय होती है, लेकिन यह एक आम किसान को होने वाली औसतन आय से बहुत कम आंकी गई है। इन अफसरों द्वारा पेश 2015-16 में संपत्ति के ऑनलाइन ब्योरे में यह खुलासा हुआ है। प्रदेश में 391 आईएएस अफसर हैं, जिनमें से 120 से ज्यादा ने अपने पास खेती की जमीन होना बताया है। इन अफसरों की राज्य के किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने का रोडमैप तैयार करने में अहम भूमिका है।

खास बात यह है कि अफसरों की रुचि भोपाल के आसपास ही खेती करने की है। अधिकतर ने भोपाल के आसपास ही कृषि जमीन खरीदी है। स्कूल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसआर मोहंती के पास भोपाल में फंदा ब्लाक के बरई ग्राम में दो एकड़ व खुदागंज में 0.275 एकड़ और उनके गृहनगर भुवनेश्वर में 8.220 एकड़ कृषि भूमि है, लेकिन इनसे कोई आय होने का उल्लेख उन्होंने अपनी सपत्ति की जानकारी में नहीं किया है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसके मिश्रा को भी भोपाल के पास स्थित सात एकड़ जमीन से कोई कमाई नहीं हो रही है। भोपाल से लगे हुए भोजपुर में संजय शुक्ल की (7.5 एकड़), डीडी अग्रवाल (4 .024 हेक्टेयर), नीतीश कुमार व्यास (1. 25 एकड़), राजेश राजोरा (चार एकड़), राजेश चतुर्वेदी (तीन एकड़), सुरंजना रे (एक एकड़), अल्का उपाध्याय (2.024 हेक्टेयर) और मलय श्रीवास्तव (2. 47 एकड़) की जमीन हैं, लेकिन आय के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है।

भोपाल के अलावा राज्य में अन्य जिलों में जिन अफसरों ने जमीन ले रखी है, वह भी खेती के लिहाज से लाभ का धंधा नहीं बन पाई। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में पदस्थ नीरज मंडलोई की खंडवा स्थित 11.595 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन उनकी संपत्ति के ब्यौरे में इससे कमाई होने का कहीं भी जिक्र नहीं है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में अपर मुख्य सचिव आरएस जुलानिया को भी इंदौर स्थित कृषि भूमि से कोई आय नहीं हुई है। मुख्य सचिव अंटोनी डिसा की उनके गृह राज्य गोवा में कृषि भूमि है, लेकिन इससे कोई आय नहीं हो रही है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव बीपी सिंह को गाजीपुर स्थित 11. 511 हेक्टेयर भूमि से कोई आय नहीं होती है।

खेती से सबसे अधिक आय अर्जित करने वालों में कृषि उत्पादन आयुक्त पीसी मीणा अन्य अफसरों से आगे हैं। मीणा की माधोपुर, रायसेन और जयपुर स्थित अपनी कृषि भूमि से लगभग 17.50 लाख की आय है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान को सहारनपुर स्थित आम के बागान से साल में साढ़े तीन लाख मिल जाते हैं। कल्पना श्रीवास्तव अपनी 7 एकड़ जमीन से 48 हजार रुपए, अनुपम राजन को एक एकड़ कृषि भूमि से 60 हजार और अजातशत्रु श्रीवास्तव को सतना और रीवा स्थित 29.31 एकड़ जमीन और एक एकड़ में फैले बगीचे से 2.85 लाख की सालाना आय हुई।

अगले कुछ वर्षों में भारत मुंहखुर की बीमारी से मुक्त हो जाएगा

मुंहखुर बीमारी फटे खुर वाले पशुओं में होने वाली आर्थिक रूप से सबसे विनाशकारी संक्रामक वायरल बीमारियों में से एक है। भारतीय कृषि शोध परिषद् (आईसीएआर) के एक अनुमान के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से इस रोग के कारण प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपये के मांस एवं दूध का नुकसान होता है। अगर अप्रत्यक्ष नुकसान को इसमें शामिल किया जाए तो यह नुकसान और भी अधिक होगा। इन अप्रत्यक्ष नुकसानों में काम की क्षमता में कमी, गर्भपात, बांझपन जैसे नुकसान हैं।

मुंहखुर बीमारी से आर्थिक हानि को रोकने के लिए स्थान विशेष आधारित मुंहखुर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 10 वीं योजना से शुरू की गई

है। धीरे-धीरे इस कार्यक्रम का विस्तार 11वीं और 12वीं योजना तक कर दिया गया। इस समय यह कार्यक्रम 13 राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों के 351 जिलों मे चल रहा है। इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगना, बिहार, महाराष्ट्र, केरल (तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, राजस्थान, पुडुचेरी, दिल्ली, अंडमान और निकोबार, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव और लक्ष्यद्वीप शामिल हैं। चरणबद्ध तरीके से इस योजना का विस्तार बाकी बचे राज्यों तक किया जाएगा जिससे उपलब्ध संसाधानों के अनुसार भौगोलिक रूप से संक्रामक क्षेत्रों में एफएमडी मुक्त क्षेत्र के निर्माण की दिशा में वांछित परिणाम मिल सके। एफएमडी-सीपी के सुदृढ़ क्रियान्वयन से वैसे राज्यों जहां एफएमडी-सीपी कार्यक्रम चलाया जा रहा था, वहां इस बीमारी में भारी कमी आई है। पूरे देश में वर्ष 2012 में जानवरों में 879 एफएमडी प्रकोप के फैलने की जानकारी दर्ज की गई थी जो वर्ष 2015 में घटकर 109 रह गई। पशु वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह यह कार्यक्रम सफल हो रहा है उससे अगले कुछ वर्षों में देश में मुंहखुर की बीमारी पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

किसान अब भूसे से भी कर सकेंगे कमाई

अभी तक किसान महज अनाज से कमाई करते थे, लेकिन अब वे भूसे से भी कमाई कर सकते हैं। कभी सिर्फ पशु आहार के तौर पर काम आने वाला भूसा आज पैसा कमाने का जरिया बन रहा है। इसकी उपयोगिता जिन्होंने जानी वे लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। किसान यदि इसे अपना लेता है तो वह केवल भूसे से लखपति बन जाएगा। जिन किसानों या व्यापारियों के पास पैसा है, वे भूसा आधारित उद्योग लगा सकते हैं और कमाई कर सकते हैं।

भूसे का सबसे अधिक उपयोग ईंधन के तौर पर होता है। सीमेंट उद्योग, कपड़ा उद्योग, बिजली संयंत्र सहित ऐसे अन्य सभी संयंत्रों में भूसे से बने व्हाइट कोल की सर्वाधिक मांग है। यह भूगर्भ में निरंतर घट रहे कोयले का पर्याप्त तो नहीं लेकिन एक बेहतर विकल्प हो सकता है। भूसे से न सिर्फ व्हाइट कोल बनाई जा रही है, बल्कि इससे पेपर नेपकिन, प्लायबोर्ड, ब्रिक्स, टायलेट नेपकिन्स आदि बनाई जा रही हैं। ईंधन की जिन उद्योगों में खासी जरूरत होती है, वहां इनकी इतनी मांग है कि वर्तमान में जो लोग इसके कारोबार में लगे हैं, वे इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। भूसा आगामी दिनों में पशु आहार में भी और अधिक मांग वाला हो सकता है, क्योंकि सरकार की नीतियां गांवों में पशु पालन को भी बढ़ावा देने की है।

भूसे के साथ ही उत्तराखंड में अब गेंहू और धान के डंठल से इथलॉन बनाया जायेगा। डंठल से इथनॉल बनाने का प्लांट उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में 35 करोड़ की लागत से लगाया जा चुका है। इसकी रोजाना क्षमता तीन हजार इथनॉल बनाने की है। इथनॉल का प्रयोग शराब बनाने में किया जाता है। यानी अब सरकार गेंहू और धान के डंठल से इथनॉल बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि किसानों की आय भी बढ़े और खेतों से निकले ठंडल से पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे।

हिमाचल के किसानों को खुद मारने होंगे बंदर

हिमाचल के किसान और बागवान दोहरी मुसीबत में फंस गए हैं। बंदर व जंगली जानवर सालभर में हिमाचल में पांच अरब रुपए की फसल नष्ट कर देते हैं। किसानों ने विभिन्न मंचों पर बंदरों व जंगली जानवरों के नुकसान से बचाने की गुहार लगाई। बड़ी मुश्किल से केंद्र सरकार ने बंदरों को वर्मिन (इंसान व खेती के लिए नुकसानदायक) घोषित किया। किसानों के मन में उम्मीद जगी कि अब राज्य का वन्य प्राणी विंग वर्मिन बंदरों को वैज्ञानिक तरीके से मारकर ठिकाने लगाएगा, लेकिन वन्य प्राणी विभाग ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। अब प्रभावित किसानों को ही फसलों के लिए खतरनाक साबित हो रहे बंदरों को मारना होगा। सरकार ने किसानों को ट्रेंड शूटर मुहैया करवाने से मना कर दिया है। यही नहीं, इस सिलसिले में वन विभाग ने प्रोटोकॉल तक जारी कर दिया है। गौरतलब है कि केंद्र की अधिसूचना के अनुसार, हिमाचल की बंदरों व जंगली जानवरों से बुरी तरह से प्रभावित 38 तहसीलों में बंदरों को वर्मिन घोषित किया गया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने यहां खतरनाक साबित हो रहे बंदरों को मारने की इजाजत दे दी थी। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी किसानों के पक्ष में आ चुका है। बाकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, लेकिन हिमाचल सरकार इससे पीछे हटी है। राज्य सरकार बंदरों को मारने का प्रोटोकॉल ही तय नहीं कर पा रही थी। अब प्रोटोकॉल तो जारी हो गया, लेकिन वन विभाग ने अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ लिया है। अब इन तहसीलों में प्रभावित किसान खुद ही बंदरों को मारने के लिए मजबूर होंगे। वन्य प्राणी विंग केवल किसानों को रेस्क्यू टीम मुहैया करवाएगा, शूटर नहीं। और तो और वन्य प्राणी विंग किसानों को बंदर मारने के लिए जरूरी हथियार भी नहीं देगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बंदर मारने में अप्रशिक्षित किसान इसमें कितना सफल होंगे। किसानों के हाथ में बंदूक थमाने के दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश में बंदरों व जंगली जानवरों के आतंक से परेशान किसानों ने कई स्थानों पर खेती से मुंह मोड़ लिया है। शिमला, सोलन व सिरमौर की कई पंचायतों में तो जमीन बंजर तक हो गई है। किसानों ने मकई व अन्य फसलें बोना छोड़ दी है। एक सर्वे के अनुसार, हिमाचल में बंदरों की संख्या करीब चार लाख है। हालांकि, राज्य सरकार ने बंदरों की नसबंदी की प्रकिया शुरू की थी, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हिमाचल के किसान केंद्र व राज्य सरकारों से इससे पहले बंदरों की साइंटिफिक किलिंग (सीयूएलएलआईएनजी) करने का आग्रह किया था। परिणामस्वरूप हिमाचल में 2006-07 में नौहराधार और सोलन में बंदर मारने के लिए ऑपरेशन साइंटिफिक कलिंग हो चुके हैं। इनके नतीजे बेहतर आए थे। इन इलाकों में बंदरों के हाथों फसलों की तबाही पर अंकुश लगा था। तभी पशु प्रेमी संगठनों ने इस मसले को उठाया। मामला अदालत में पहुंचा और बाद में हाईकोर्ट ने बंदरों के मारने पर रोक लगाई थी। फिलहाल इन दिनों ये रोक भी हट चुकी है। हिमाचल में बंदरों की बढ़ती संख्या और उनके उत्पात से निपटने के लिए वन विभाग ने बंदरों को पकड़ने का सिलसिला शुरू किया था। एक बंदर पकड़ने पर वन विभाग पांच सौ रुपए देता है। पकड़े गए बंदरों की नसबंदी की जाती है, ताकि इनकी संख्या नियंत्रित हो। बंदरों का उत्पात तो घटा नहीं, उल्टा बंदर पकड़ने वाले लखपति हो गए।

वैसे अब किसानों व बागवानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना आरंभ की गई है, जिसके तहत सौर ऊर्जा चलित बाड़ लगाने का प्रावधान है। जोकि किसानों की फसलों को जानवरों से बचाएगा। इस बाड़ से करंट छोड़ा जाएगा जिससे फसलों को तबाह करने वाले जानवर खेतों में नहीं जा पाएंगे। उप निदेशक कृषि डा. रतन सिंह ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना किसानों व बागवानों के लिए 60 प्रतिशत अनुदान पर चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सौर चलित ऊर्जा बाढ़ से खेतों के चारों ओर सौर चालित बिजली की पांच से नौ तारें एक-एक फुट की दूरी पर लगेंगी, जिसमें यदि जंगली जानवर खेतों में जाने की कोशिश करता है तो उस जानवर को केवल 0.1 सेंकंड के लिए 10एमए का जोरदार झटका लगेगा, जिससे वह पीछे की ओर हटेगा, परंतु इस झटके से उसकी जान को कोई खतरा नहीं है और इसी तरह हर सेकेंड में करंट छोड़ता रहेगा। लोगों को छूने के बावजूद थोड़ा झटका जरूर लगेगा, लेकिन इससे जान का जोखिम नहीं होगा। इसके अंतर्गत इसमें करंट कम व ज्यादा करने की भी सुविधा है।

मनौली के किसान चले कृषि पर्यटन की ओर

कृषि तकनीक के लिए देशभर में मशहूर हो चुके सोनीपत जिले के मनौली गांव के किसान अब खेती पर्यटन के जरिये नई पीढ़ी को बेहतर और तकनीकी खेती की जानकारी देंगे। इसके लिए यहां के किसानों ने एक कारोबारी समूह के साथ मिलकर खेती पर्यटन का स्पॉट सोनीपत में विकसित किया है। यह खेती पर्यटन कोई ऐसी-वैसी नहीं, बल्कि फूल प्रूफ खेती पर आधारित पर्यटन का अनूठा पिकनिक स्पॉट यहां बनाया गया है। इसके जरिये खेती को नया लुक और आधुनिक तौर-तरीका देने का प्रयास किया गया है। स्वीफ्ट कार्न के लिए चर्चित इस गांव के युवा प्रगतिशील किसान दिनेश कुमार व उसके साथ अरूण चौहान की टीम ने यह बीड़ा उठाया है। इसमें इन्हें तारेश वर्मा का बिजनैस ग्रुप हैड के रूप में साथ मिला है। इसमें सारा पैसा और टूरिज्म का प्लान तारेश का रहेगा और किसानों का ज्ञान और तकनीक लोगों को खेती से रूबरू कराएगा। अपने किस्म का देश

का यह पहला अनूठा केंद्र होगा, जहां स्वीमिंग पुल होगा और लजीज व्यंजनों की कैंटीन भी, लेकिन यहां आने वाले हर आदमी को खेती जरूर करनी होगी, ताकि वह जमीन से जुड़कर खुद यह जांचे की खेती कैसे होती है और इसके लिए क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है।

मनौली में माई प्ले फार्म के नाम से शुरू किया गया यह सेंटर करीब चार एकड़ में फैला हुआ है। यह सारा सिस्टम ऑनलाइन है। इसमें माई प्ले फार्म की वेबसाइट के जरिये लोग अपना आदेवन करते हैं और इसके जरिये पूरा प्रोग्राम चलता है। इसमें मोटे तौर पर एक आवेदन को दस गुना दस गज का प्लाट यहां दिया जाएगा। इस फार्म में सप्ताह के दो दिन से लेकर सातों दिन तक फसल की देखभाल कर सकते हैं।

एलपीजी सब्सिडी पर सरकार की खुली पोल

केंद्र का दावा है कि रसोई गैस सब्सिडी पर उसके नए अभियान से वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 में होने वाली बचत का आंकड़ा करीब 22 हजार करोड़ रुपये तक जाएगा। यह अभियान दो स्तरों पर चलाया जा रहा है। एक तरफ उपभोक्ताओं तक उनके बैंक खाते के जरिये सब्सिडी सीधे पहुंचाई जा रही है, दूसरी ओर सक्षम उपभोक्ताओं से कहा जा रहा है कि देशहित में वे खुद ही सब्सिडी छोड़ दें। इसे गिव इट अप अभियान के नाम से प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन कैग की एक रिपोर्ट इस दावे की हवा निकालती दिखती है। इसके मुताबिक प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण (डीबीटी) और स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने वाली योजना से होने वाले फायदे का आंकड़ा दो हजार करोड़ रुपये से भी कम है। बाकी करीब 20 हजार करोड़ रुपये की बचत इसलिए हुई है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दामों में नाटकीय रूप से भारी गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, कैग के ऑडिट के दौरान डीबीटी योजना में बड़ी व्यवस्थागत खामियां भी पाई गई हैं। जैसे घरेलू एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी को व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल होने वाली एलपीजी पर दिया जा रहा है। डीबीटी योजना मोदी सरकार ने नवंबर 2014 में शुरू की थी। इसके तहत सब्सिडी की रकम सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेज दी जाती है। 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि डीबीटी और गिव इट अप अभियान से दलालों और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को चोट पहुंची है जिससे गैस सब्सिडी के नाम पर हर साल होने वाली 15 हजार करोड़ रुपये की चोरी रुकी है। लेकिन, कैग रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। इसके मुताबिक सब्सिडी के बजट में आई गिरावट में बड़ी भूमिका अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में आई भारी कमी की है। भारत बड़ी मात्रा में एलपीजी का आयात करता है। सरकार की पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनैलिसिस सेल के मुताबिक, 2014-15 में सरकार को इस आयात के लिए 36,571 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े थे, जबकि 2015-16 में यह आंकड़ा गिरकर 25,626 करोड़ रुपये हो गया। यानी कीमतों में कमी के चलते एक साल में 10,945 करोड़ रुपये की बचत अपने आप ही हो गई। दिलचस्प बात यह भी है कि ऐसा इस दौरान एलपीजी का आयात बढ़ने के बावजूद हुआ। पहले साल यह 8313 हजार मीट्रिक टन (टीएमटी) था तो दूसरे साल यह 8885 टीएमटी हो गया।

राजस्थान एग्रीटेक मीट के लिए देशभर में रोड शो

राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर में जयपुर में आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2016 (ग्राम) के प्रचार-प्रसार के लिए पहला रोड शो जब मुम्बई में आयोजित हुआ, तो राज्य के कृषि मंत्री प्रभु लाल सैनी फूले नहीं समां रहे थे। इसके बाद उन्होंने देश के आठ शहरों में इस तरह के रोड शो आयोजित किए गए। रोड शो में गए प्रतिनिधिमंडल ने रोड शो के दौरान निवेशकों और प्रतिभागियों को ग्राम के उद्देश्यों के बारे में बताएगा। ग्राम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में त्वरित और सतत विकास के माध्यम से किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना तथा 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करना है। प्रत्येक रोड शो के दौरान ग्राम पर एक लघु फिल्म, पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन और इन्वेस्टर्स गाइड के जरिए राजस्थान में कृषि क्षेत्र में उपलब्ध निवेश के अवसरों के बारे में बताया गया और राज्य को पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त रोड शो के जरिए हितधारकों को राज्य के कृषि एवं अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में लागू नए अधिनियमों, अनुदानों एवं नीतियों की जानकारी दी जाएगी। राज्य के कृषि मंत्री प्रभु लाल सैनी ने कहा कि राजस्थान में दस प्रकार के जलवायु संबधिंत परिक्षेत्रों की विशिष्ट परिस्थितिकी तंत्र के कारण प्रदेश में कृषि विकास की असीम संभावना है। इसके लिए हमें अपनी चुनौतियों को सुअवसरों में बदलने की आवश्यकता है।

बारिश के बाद भी कुछ राज्यों में रहेगा सूखा

मौसम विभाग देश में सामान्य मानसून का पूर्वानुमान भले जाहिर करे, पर शोध एवं सलाह कंपनी क्रिसिल का मानना है कि कुछ राज्यों में सूखा रह सकता है। क्रिसिल कंपनी ने अपने एक शोध पत्र में सूखे की बात उठाई है। पिछले दो साल से पूरे देश में खराब मानसून के कारण काफी कम बारिश हुई है, लेकिन इस साल सामान्य से अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। क्रिसिल ने ड्रिप्स ऑफ होप नामक शोधपत्र में बताया है कि गुजरात और ओडिशा में सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जबकि असम, हिमाचल प्रदेश और केरल में भी हालत मुश्किल रह सकती है। इसके अलावा उसने आठ राज्यों के 89 जिलों में ज्यादा बारिश की आशंका जताते हुए कहा है कि इसके कारण इन क्षेत्रों में खरीफ फसल की उपज प्रभावित हो सकती है। क्रिसिल ने कहा कि इस साल जून में मानसून की कमजोर शुरूआत हुई लेकिन इसके बाद हुए सुधार के कारण बारिश अधिक हुई और जुलाई तक यह सामान्य स्तर से मात्र एक फीसद कम रही। बेहतर बारिश से जमीन के नीचे के पानी के स्तर के साथ ही अन्य जल स्रोतों के भंडार में सुधार हुआ, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद बढ़ गई है। उसने कहा कि चालू वित्त वर्ष में कृषि उत्पादन में चार फीसद से अधिक की दर से विकास की उम्मीद है, जिससे देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर बढ़कर 7.9 फीसद पर पहुंच जाएगी। उसने इस दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) महंगाई दर के पांच फीसद पर स्थिर रहने की भी उम्मीद जताई है।

एक रुपये में 10 लाख का बीमा

भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) रेल यात्रियों के लिए बीमा योजना शुरू की है। 31 अगस्त से शुरू हुई इस बीमा योजना में रेल यात्रियों का महज एक रुपए में 10 लाख रुपए का बीमा होगा। तीन बीमा कंपनियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बीमा की यह राशि

रेल दुर्घटना की स्थिति में मिलेगी। शर्त बस इतनी है कि यात्री के पास आईआरसीटीसी से बुक किया हुआ ई-टिकट होना चाहिए और उसे बुक करवाते वक्त यात्री ने बीमा कवर लिया हो। यात्री के साथ यदि पांच साल से कम उम्र का बच्चा सफर कर रहा है तो ई-टिकट आरक्षण फार्म पर यात्री उसका ब्यौरा जरूर दे। तभी बच्चा भी बीमा का हकदार होगा, वरना नहीं। सफर के दौरान यदि रेल दुर्घटना होती है और किसी यात्री की जान चली जाती है और उसने ई-टिकट पर बीमा कवर लिया हुआ है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए मिलेंगे। यात्री यदि स्थाई रूप से पूरी तरह दिव्यांग हो जाता है तो उसे भी 10 लाख रुपए बीमा राशि के रूप में मिलेंगे। यात्री के शरीर का कोई अंग स्थाई रूप से दिव्यांग हो जाता है तो उसे 7.50 लाख और मामूली रूप से जख्मी होने पर 2 लाख रुपए की राशि बीमा कंपनी की ओर से दी जाएगी। साथ ही शव ले जाने के लिए भी 10 हजार रुपए अलग से दिए जाएंगे। आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. एके मनोचा ने बताया इसके लिए हमने टेंडर जारी किया और बीमा क्षेत्र की 19 कंपनियां चयनित की गई, लेकिन आईआरडीए के नियमों के मुताबिक बेहतर बोली देने वाली प्रमुख तीन कंपनियों को यह जिम्मेदारी दी गई। इनमे श्रीराम, आईसीआईसीआई और रॉयल सुंदरम शामिल हैं।

कृषि विभाग का भी नाम बदला

हरियाणा में जब से मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनी है, तब से राज्य में भले ही कुछ बदला हो या न बदला हो, लेकिन कई पुराने नाम जरूर बदल गए। गुड़गांव अब गुरुग्राम हो चुका है, हालांकि यहां के बाशिंदे अब भी गुड़गांव ही बोल रहे हैं। उन्हें गुरुग्राम नाम न तो पसंद आ रहा है और न ही वे इसे अपनाने के मूड में हैं। ऐसे में, स्थानीय प्रशासन का हाल समझा जा सकता है। खैर, अब हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कृषि विभाग का नया नामकरण किया गया है। अब इस विभाग को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नाम से जाना जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने प्रदेश के सभी डीसी सरकारी कार्यालयों को लिखित सूचना भिजवा दी है और भविष्य में कृषि विभाग से संबंधित कोई भी पत्राचार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नाम से किया जाएगा।

नदी किनारों के विकास पर 50,000 करोड़ रूपये खर्च होंगे– गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भारत 20,000 किलोमीटर लंबे शहरों को छूते नदी किनारों तथा 7500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट के विकास की तैयारी में है और इस पर 50,000 करोड़ रुपये का शुरुआती निवेश किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि जलमार्ग उत्तर प्रदेश के विकास का इंजिन साबित होंगे। हम 20,000 किलोमीटर नदी किनारों तथा 7500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट का 50,000 करोड़ रुपये के निवेश से विकास करेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग-1 का विकास जल मार्ग विकास परियोजना के जरिए किया जा रहा है। यह परियोजना विश्व बैंक की मदद से लागू की जा रही है। इस पर 4200 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इससे वाराणसी से हल्दिया तक गंगा के जरिए भारी पोतों की आवाजाही सुनिश्चित होगी। गडकरी ने कहा कि जलमार्गों के जरिए कारों के परिवहन से पश्चिम बंगाल में इनकी लागत 5000 रुपये तक कम होगी। मंत्री ने कहा कि जलमार्गों के प्रोत्साहन से केवल उत्तर प्रदेश में ही चार से पांच लाख रोजगार पैदा होंगे। गडकरी ने कहा कि मोदी सरकार खाली बातों में ही विश्वास नहीं करती, बल्कि जो कहती है उसे वास्तविकता में बदलती है। गंगा को परिवहन योग्य बनाने की मौजूदा परियोजना इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि संसद ने देश भर की 111 नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने संबंधी एक महत्वपूर्ण विधेयक इसी साल पारित किया है। अब तक केवल पांच नदी खंडों को ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। सरकार इस दिशा में त्वरित काम के लिए प्रतिबद्ध है।

नया रायपुर में फाइव स्टार ग्रीन बिल्डिंग

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने बीते दिनों नया रायपुर के सेक्टर-19 में लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 'पयार्वास भवन' का लोकार्पण किया। यह छत्तीसगढ़ की पहली फाइव स्टार ग्रीन बिल्डिंग है। लगभग 15 हजार वर्गमीटर में निर्मित पांच मंजिला यह भवन नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल और गृह निर्माण मंडल का संयुक्त कार्यालय भवन है। तीन साल पहले 22 अप्रैल 2013 को इस भवन का शिलान्यास किया गया था। भवन में 200 किलोवॉट का सौर ऊर्जा पैनल और रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है। ग्रीन बिल्डिंग की परिकल्पना के अनुसार, इस भवन में सूर्य के प्रकाश और सौर ऊर्जा से पैदा होने वाली बिजली का उपयोग किया जाएगा। इस भवन में एनआरडीए, पर्यावरण संरक्षण मंडल व गृह निर्माण मंडल के अलग-अलग खंड हैं और अंदर से तीनों खंडों को गलियारे से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि सुविधायुक्त कार्यस्थल से कर्मचारियों व कार्यालय आने वाले लोगों को कामकाज में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी की परिकल्पना के आधार पर विकसित हो रहे नया रायपुर के इस भवन में सुविधापूर्ण और बेहतर वातावरण मिलेगा। राज्य के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि एनआरडीए, पर्यावरण संरक्षण व गृह निर्माण मंडल के कार्यालय एक ही छत के नीचे होने से नई राजधानी के विकास में और तेजी आएगी।

17 देशों के कृषि पेशेवरों को प्रशिक्षित करेंगे भारत और अमेरिका

भारत और अमेरिका ने एक वैश्विक कार्यक्रम के दूसरे चरण की पेशकश की है, जिसके तहत अफ्रीका और एशिया भर के 17 देशों के 1,500 कृषि पेशेवरों को अगले चार वर्षों में नई कृषि तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। फीड द फ्यूचर इंडिया ट्रैंगुलर ट्रेनिंग कार्यक्रम को सरकार के राष्ट्रीय कृषि विस्तार संस्थान (एमएएनएजीई) और अंतरराष्ट्रीय विकास अमेरिकी एजेंसी (यूएसएआईडी) के द्वारा लागू किया जायेगा। पहले चरण में 2013-15 के दौरान तीन अफ्रीकी देशों कीनिया, लाइबेरिया और मालावी के 219 पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया। वे अब कृषि उत्पादकता और आय को बढ़ाने के लिए खेती के नए तरीकों को लागू कर रहे हैं। कृषि सचिव एस. के. पटनायक ने पेशकश के बाद कहा कि पहले चरण का प्रभाव काफी संतोषजनक है और कार्यक्रम का विस्तार और अधिक देशों तक फैलाने के लिए किया गया है। इसलिए, दूसरे चरण में अफ्रीका और एशिया के 17 देशों को अपने दायरे में लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि 15 दिनों की अवधि वाले करीब 32 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन भारत में किया जायेगा और 10 दिनों तक चलने वाले करीब 12 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन अफ्रीकी और एशियाई देशों में 2016 से 2020 के दौरान किया जाऐगा।

पटनायक ने कहा कि भागीदारी करने वालों

का यात्रा, बीमा, रहने, स्थानीय यात्रा और कार्यक्रम शुल्क सहित पूरा खर्च यूएसएआईडी और एमएएनएजीई द्वारा वहन किया जाएगा। भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा ने कहा कि दो महान देशों की विशेषज्ञयता और अन्वेषण का उपयोग करते हुए हम वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान के लिए नए अवसरों का सृजन कर रहे हैं तथा इस तरह हम दुनिया को गरीबी और भुखमरी से मुक्त करने के अपने साझा दायित्वों के निर्वहन में एक दूसरे के और करीब आये हैं। अफ्रीका में कीनिया, लाइबेरिया, यूगांडा, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मोजाम्बिक, तंजानिया, सूडान, बोत्सवाना, इथियोपिया और एशिया में अफगानिस्तान, कोलम्बिया, लाओं पीडीआर, म्यांमा, मंगोलिया और वियतनाम जैसे 17 देशों के कृषि पेशेवरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृषि विस्तार प्रबंधन में सार्वजनिक निजी भागीदारी पर कार्यक्रम का पहला चरण हैदराबाद स्थित एमएएनएजीई द्वारा 17 से 31 अक्तूबर के दौरान किया जायेगा। फलों और सब्जियों के विपणन में उभरती प्रवृत्तियों पर कार्यक्रम का दूसरा चरण जयपुर स्थित राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान द्वारा 16 से 30 नवंबर के दौरान किया जायेगा।

शुभ साबित हो रही हैं झारखण्ड सरकार के लिए मछलियां

सामान्य तौर पर मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए प्रसिद्धी पाने वाले झारखंड की पीठ एक और बात के लिए ठोकी जा रही है। वह है सूबे में मछली उत्पादन को लेकर विकसित किया गया केज कल्चर। इस पद्धति से न केवल राज्य का मछली उत्पादन बढ़ा है, बल्कि इसके मॉडल को कई राज्यों के लोगों ने आकर देखा है और अपने यहां उपयोग भी किया है। पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के निदेशक राजीव कुमार ने बताया कि करीब दो दर्जन राज्यों के अधिकारियों ने यहां आकर इसकी जानकारी ली है। इसकी शुरूआत 2011 में रांची के हटिया डैम में की गयी थी। फिलहाल राज्य के चांडिल, कोनार, तिलैया, मसानजोर डैम समेत अन्य जल स्त्रोतों में करीब 2800 केज कल्चर के यूनिट है। कुमार ने बताया कि आने वाले वर्ष में केवल केज कल्चर से लगभग 40 हजार मीट्रिक टन मछलियों के उत्पादन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2017-18 तक लिए लगभग 10,000 केज बनाने होंगे। केज कल्चर के तहत मछली पालन के लिए किसानों को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक करीब 8500 से अधिक मछली उत्पादक इसकी ट्रेनिंग ले चुके हैं। इसके प्रमोशन के लिए राजधानी के धुर्वा इलाके में बाकायदा एक मत्स्य निदेशालय काम कर रहा है। मछली पालन के लिए यह प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया था। इसके तहत पानी में जाल डाला जाता है जो पिंजरे के सामान होता है। तीन तरह का केज कल्चर होता है। इसके तहत स्क्वायर फ्रेम के रूप में चार तरफ ड्रम बंधे होते हैं। उन्हें आयरन रोड से एक दूसरे से बांध कर उनके चारों सिरों पर जाल बांध दिया जाता है। जाल तालाब की पूरी गहराई तक होता है। फिर उसमे मछली का जीरा डाला जाता है। जब यह जीरा बड़ा होता है तब इसे तालाब में डाला जाता है। यह जाल पानी के अन्दर रहता है ताकि मछलियां आराम से केज के अन्दर अपनी चहलकदमी बरकरार रखें। अनुमान के हिसाब से प्रति केज तीन से चार टन मछली का उत्पादन होता है।

राज्य गठन के वक्त मछली उत्पादन 14,000 मैट्रिक टन था जो पिछले साल बढ़कर 1.20 लाख मैट्रिक टन हो गया। हालांकि पिछले पन्द्रह सालों में उत्पादन बढ़ा है। फिर भी यह आवश्यकता से 20 हजार मैट्रिक टन कम है। मौजूदा मांग 1.40 लाख मैट्रिक टन की है। इस अंतर को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश से मछलियां मंगाई जाती है।

दिल्ली में पेड़ों से पैदा होगी बिजली

देश की राजधानी दिल्ली में बिजली की कमी न हो, इसके लिए सरकार सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर बिजली पैदा करेगी। बता दें कि इसके लिए दिल्ली के कई इलाकों में एक खास किस्म के पेड़ लगाए जाएंगे, जो इन इलाकों में बिजली पैदा करेंगे। एक ऐसे ही सोलर पेड़ को बीते दिनों विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्द्धन के सरकारी आवास पर लॉच किया गया है। ये बनावटी पेड़ पुराने किस्म के पैनलों से ज्यादा असरदार तरीके से सौर ऊर्जा पैदा करके बिजली बनाता है। इसे काउंसिल फॉर साइंटिफीक एंड इंडस्ट्रिल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने बनाया है और इस पर तकरीबन पांच लाख का खर्च आया है। सौर ऊर्जा का हब बनने का सपना पूरा करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक पेड़ की शक्ल में 20 सोलर पैनल पांच घरों को बिजली दे सकते हैं। इतनी ही बिजली देने वाला परंपरागत सौर ऊर्जा जनरेटर सौ गुना ज्यादा जगह घेरता है, जबकि इसे एक वर्गमीटर से कुछ ज्यादा ही जगह की जरूरत होती है। इस तरह के पेड़ की जिंदगी 25 साल तक हो सकती है और इसे हाइवे के किनारे या खेतों में भी लगाया जा सकता है।

केजरीवाल पर भड़के किसान

दिल्ली में आप सरकार बड़े-बड़े वादों के साथ सत्ता में आई और जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दिल्ली के नरेला विधानसभा के पल्ला गांव के किसानों को केजरीवाल सरकार से शिकायत है, जबकि बाहरी दिल्ली इलाके में यमुना किनारे बसे सौ से ज्यादा गांवों के किसान खेती करते हैं। उनकी जीविका भी खेती की फसलों पर निर्भर करती है। किसानों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि जब से दिल्ली में केजरीवाल सरकार आयी है, उन्होंने आते ही किसानों के लिए खेती की बिजली की दर बढ़ा दी। शीला सरकार के समय में बिजली की जो दर थी, अब उससे कई गुना बढ़ोत्तरी केजरीवाल सरकार ने कर दी है। सरकार ने किसानों के खेतों में पंपिंग सेट बिजली के कनेक्शन कमर्शियल कर दिए और अब किसानों का बिजली का बिल 40-40 हजार रुपये आ रहा है। किसानों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी सरकार किसानों का शोषण कर रही है। दिल्ली में सौ से ज्यादा गांव खेती कर रहे हैं, जो एकजुट होकर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे।

स्वच्छता के बाद मंडी का विकास अभियान बना मॉडल

स्वच्छता अभियान में देश में अव्वल रहे हिमाचल के मंडी जिले का विकास अभियान भी अब मॉडल बनकर उभरा है। जिले में स्वच्छता के अलावा सुक्ष्म बीमा और स्वयं सहायता समूहों के संचालन में महिलाओं की भागीदारी एक जनांदोलन के रूप में हुई है। 25 अगस्त को दिल्ली के मौर्या होटल में आयोजित एक कार्यक्रम में मंडी के उपायुक्त संदीप कदम ने जिले के विकास अभियान और स्वच्छता की सफलता को लेकर प्रस्तुति दी। मंडी जिला, प्रदेश का ऐसा एकमात्र जिला बन गया है, जिसकी 469 पंचायतें खुलाशौच मुक्त घोषित हो चुकी हैं। लोगों ने अपने दम पर जिला के 243322 घरों में शौचालयों का निर्माण कर उनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। मंडी जिला में चल रहे विकास अभियान में स्वच्छता प्रमुख मुददा होने की वजह

से उपायुक्त संदीप कदम को राष्ट्रीय स्तर पर गठित 20 राज्यों के चैंपियंस स्वच्छता अधिकारी क्लब में शामिल किया गया है। यह क्लब स्वच्छता अभियान में पिछड़ रहे राज्यों को अपने यहां चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी देकर सफलता के टिप्स भी देगा। 25 अगस्त को दिल्ली में हुए स्वच्छता कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की।

बीज के अभाव में डालियों को बना दिया पेड़

निरंतर घट रहे जंगल को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के वन महकमे ने अनोखा प्रयोग किया है। हरियाली बढ़ाने के लिए पेड़ों की डाल को काटकर उन्हें जंगल में रोपा जा रहा है। इसे कलम विधि कहा जाता है। अब तक इस विधि का प्रयोग बाग-बगीचों में फूलों के पौधे लगाने के लिए होता आया है, लेकिन यह पहली बार है कि जंगली पेड़ों की डालियां रोपकर उन्हें पेड़ बना दिया गया। तीन माह पूर्व 1200 डाल (शाख) जंगल में तीन जगह रौंपी गईं, उनमें से 650 से ज्यादा डालियां पेड़ बन गई हैं। इस सफल प्रयोग का आइडिया भी खुद श्योपुर के डीएफओ सीएस निनामा का है।

जिले के वनों में सलाई (सालेय) के पेड़ों की संख्या बहुतायत में है, तो यहां की मिट्टी इन पेड़ों को रास भी आती है। यह देखने के बाद डीएफओ निनामा को सालेय के पेड़ों की संख्या बढ़ाने की सूझी, लेकिन सालेय के पौधे या बीज आसानी से नहीं मिल पा रहे थे। इसके बाद निनामा ने वनकर्मियों से उन सालेय के पेड़ों की डालें कटवाने को कहा जो अच्छी तरह पनप गए हों। वन विभाग के कर्मचारियों ने पेड़ों की 1200 से ज्यादा डालियां काटी। इन्हें पांच से छह फीट की लंबाई में काटा गया। मई महीने में खुद सीएस निनामा ने खड़े होकर अपनी निगरानी में कालीतलाई गांव और ईको सेंटर के पेड़ों की इन डालों को जमीन में लगवाया। एक से डेढ़ फीट गहरे गड्ढे करने के बाद उनमें गोबर-मिट्टी मिलाकर डाली गई। फिर डालों को इन गड्ढों में रौपा गया। ढाई से पौने तीन महीने पहले लगाई गईं पेड़ों की डालों में से आधे से ज्यादा तीन से चार फीट लंबे पेड़ बन गए हैं। जंगल के कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनके बीज आसानी से नहीं मिल पाते, इसलिए इनके पौधे भी कम मिलते हैं। कृषि और उद्यानिकी की किताबों में कई पेड़ों का जिक्र हैं, जिनकी डालों को काटकर कलम विधि से रोपा जाए तो वह पेड़ बन जाती हैं। इनमें सलाई का पेड़ भी शामिल है। किताबों में लिखी इस जानकारियों पर कभी किसी ने अमल नहीं किया। श्योपुर वन विभाग ने पहली बार यह प्रयोग किया है जिसके रिजल्ट देख वन अफसर गदगद हैं और इस प्रयोग को अन्य पेड़ों पर आजमाने की सोच रहे हैं।

झारखंड के किसानों का हाल नोएडा के किसानों की तरह होने वाला है

झारखंड सरकार सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन करके यहां के आदिवासियों और मूलवासियों की जमीन उसी तरह छीन कर उद्योगपतियों को सौंप देना चाहती है, जैसा कि एक समय उत्तर प्रदेश में नोएडा के किसानों के साथ हुआ था।' झारखंड सरकार पर यह आरोप पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगाया है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल के अधिकतर सदस्य इन दोनों एक्ट में संशोधन के खिलाफ हैं। इस वजह से सरकार इस पर चर्चा से बचने के लिए अध्यादेश लेकर आयी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हर स्तर पर इसका विरोध करेगी। उन्होंने बताया कि इस एक्ट के रहते हुए कोल इंडिया, टाटा, एनटीपीसी सहित कई बड़े उद्योग काम कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह के संशोधन करके सरकार केवल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा राज्य में उद्योपतियों को बुलाने के लिए दूसरे राज्यों में किए जा रहे दौरे को जनता के पैसे की बरबादी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में छोटे-छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं।

किसानों के लिए हरित घोषणा-पत्र

वातावरण और समाज बचाओ मोर्चा पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियों को हरित घोषणा-पत्र (ग्रीन मेनिफेस्टो) सौंपेगा और मांग करेगा कि पार्टियां जब भी अपना घोषणा-पत्र तैयार करें, उसमें पानी, जमीन और खेती को रासायनिक खादों से बचाने के लिए कार्यक्रम भी दें। कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा ने किसानों के लिए आय आयोग बनाने की वकालत करते हुए कहा कि किसी भी किसान को 18,000 रुपए प्रति महीने से कम नहीं मिलना चाहिए। किसानों के पास पैसा होगा तो देश के औद्योगिक विकास को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने पंजाब में गैर-रसायनिक खेती को बढ़ावा देने की मांग करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश पिछले 12 सालों से इस ओर आगे बढ़ रहा है और अब तक वहां की सरकार ने 36 लाख हेक्टेयर जमीन को गैर-रसायनिक खेती में बदल दिया है। उनका लक्ष्य अपनी सारी 56 लाख हेक्टेयर जमीन को आर्गेनिक में बदलने का है। आर एस घुम्मण ने कहा, सरकार की प्राथमिकताएं ही अलग हैं। पानी और जमीन खराब हो रही है सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है लेकिन करोड़ों रुपए स्मारकों पर लगाने के लिए सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। डॉ अतर सिंह आजाद ने जमीन के जहरीली होने से इसका स्वास्थ्य पर हो रहे असर को लोगों के साथ साझा किया, जबकि प्रसिद्ध पत्रकार गोबिंद ठुकराल ने कहा कि हरित घोषणा-पत्र को लागू कराना ही हमारा उद्देश्य है। खेती विरासत मिशन के कार्यकारी डायरेक्टर उमेंद्र दत्त ने कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का ध्यान इस ओर नहीं है कि उनकी नीतियों के कारण पंजाब का वातावरण खराब हो रहा है। रासायनिक खादों से पानी प्रदूषित हो चुका है, जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो चुकी है।

हनी के गाने बजाओ, सुअर भगाओ

जंगली जानवरों के आतंक से उत्तराखंड के किसान और सरकार दोनों ही लंबे समय से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा इससे निपटने के लिए कई कदम भी उठाए गए, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। आखिरकार इससे परेशान होकर एक किसान ने एक अनोखा हल निकाला। सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सच है कि नैनीताल के किसान बिशान जंतवाल, हनी सिंह और पंजाबी गायकों के गाने ऊंची आवाज में चलाकर सुअरों को भगा रहे हैं। इन गानों से न केवल जंगली सूअर बल्कि दूसरे जानवर भी उनके खेतों में नहीं आते हैं। दरअसल नैनीताल के धारी गांव के रहने वाले 48 साल के किसान बिशन जंतवाल ने बताया कि उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि जंगली जानवर वहां आने से कतराते हैं, जहां इंसान रहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने खेतों में लाउडस्पीकर लगाकर हनी सिंह और पंजाबी गायकों के गाने ऊंची आवाज में चलाए। इसके बाद आस-पास के कई गांववालों ने भी इस तरकीब को काम लिया तो उनके लिए भी सफल साबित रही। आपको बता दें कि नैनीताल में जंगली सूअर के आतंक से बचने के लिए राज्य सरकार ने उन्हें मारने के आदेश भी दे दिए थे, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं पड़ा। गौरतलब है कि पिछले साल जानवरों ने आलू, टमाटर और गेहूं की खेती को इतना नुकसान पहुंचाया था कि यहां के कई किसान दिवालिया हो गए। लेकिन, नैनीताल में बिशन जंतवाल के आइडिया की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है।

भिखारियों के लिए नौकरी

राजस्थान के एक युवक ने बेहद अनूठे विचार पर स्टार्टअप शुरू किया है। इस युवक की योजना में भिखारियों को ही नौकरी पर रखा जाता है। खास बात ये है कि इस युवक ने योजना को अपनाने के लिए सरकार को भी सुझाव दिया था, लेकिन कोई सकारात्मक रुख नजर नहीं आने पर इसे खुद शुरू करने का फैसला लिया। नई सोच और अनूठी योजना पर काम करने वाले हैं सीकर जिले के श्रीमाधोपुर उपखंड के मंडरू गांव निवासी गणपत यादव। गणपत ने बताया कि उन्होंने जैविक खेती पर काम शुरू किया है और इसके लिए जयपुर के चौमूं के नजदीक खेजरोली और सिंगोद गांव में दो अलग-अलग जमीन लीज पर ली हैं। गणपत का कहना है कि भीख मांगने से जुड़े लोगों को वे इस योजना में न सिर्फ काम करने के लिए जोड़ेंगे, बल्कि उनके तमाम तरह के खर्चों को भी वे ही वहन करेंगे। उनका कहना है कि वे इनको इस तरह से नौकरी पर रख रहे हैं जिसमे इनके खाने-पीने-रहने से लेकर जैविक खेती की ट्रेनिंग तक का काम इन्हीं के खर्चे पर होगा। यही नहीं यहां काम करने वालों के बच्चों की पढ़ाई के खर्चे का जिम्मा भी उठाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा एक रजिस्टर्ड संस्था बनाई गई है। गणपत सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए अपने तमाम परिचितों को सड़कों पर भीख मांगते दिख रहे व्यक्ति को उनसे संपर्क करवाने और उन्हें नौकरी पर लगाने का भरोसा दिला रहे हैं।

गणपत का कहना है कि बचपन से ही उनका सपना था कि वे सड़कों पर भीख मांगकर गुजर-बसर करने वालों और अन्य कारणों से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की किसी तरह मदद करें। ऐसी मदद जिससे उन्हें अपने पांव पर खड़े होने का संबल मिल सके। इंजीनियरिंग करने के बाद वैसे तो गणपत की निजी कंपनियों में लाखों रुपये की नौकरी लगी, लेकिन कुछ साल तक नौकरी करने के बाद वे अपना बचपन का सपना पूरा करने गांव आ गए। फिलहाल उनका मकसद सौ से ज्यादा लोगों को अपनी योजना से जोड़कर उन्हें आत्मसंबल बनाने का है। उन्होंने कुछ भिखारियों को अपने साथ जोड़ लिया है और फिलहाल बाजरे का चारा, सब्जियां, मूंगफली जैसी अन्य पैदावार की जा रही हैं।

उत्तराखंड 18 प्रतिशत की उच्च वृद्धि हासिल करेगा- हरीश रावत

पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि देश के 7-8 सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले राज्यों में उत्तराखंड भी शामिल है और 2018-19 तक हम लगभग 18 प्रतिशत की उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल करेंगे। उत्तराखंड में समावेशी विकास का जिक्र करते हुए रावत ने कहा कि जब उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला तब राज्य की प्रति व्यक्ति आय 84,000 रुपये सालाना थी, जो कि अब बढ़कर दो लाख रुपये प्रति व्यक्ति तक पहुंच गई है। उन्होंने राज्यों को और आजादी दिये जाने पर भी जोर दिया और कहा कि केन्द्र को राज्यों को अपना भागीदार मानना चाहिये। उन्होंने कहा कि केन्द्र को राज्यों को अधिक आजादी देनी चाहिये। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मुख्यमंत्रियों को अपना छोटा भाई समझना चाहिये। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली सबसे सस्ती है, राज्य 24 घंटे बिजली आपूर्ति का वादा करता है। राज्य में लघु पनबिजली परियोजनाओं और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में महिला उद्यमियों को विशेष तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। हथकरघा, हस्तशिल्प सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले तीन साल में राज्य में कम से कम दस हजार महिलाओं को इस कदर दक्ष बनाया जायेगा कि वह उद्यमी बन जायेंगी। उन्होंने राज्य में महिला उद्यमियों को सस्ती दर पर जमीन उपलब्ध कराने के एफएलओ के सुझाव विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों द्वारा शुरू की गई इकाइयों के लिये एकल खिड़की योजना शुरू करने का भी आश्वासन दिया।

रेशम उद्योग को बढ़ावा देकर लोगों को रोजगार- अजय टम्टा

केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि उनका मंत्रालय अब उत्तराखण्ड में जल्द ही रेशम उद्योग को बढ़ावा देकर यहां के लोगों रोजगार देगा। उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार उत्तराखण्ड के बुनकरों और उद्योग के लिये 6 प्रतिशत अनुदान देगी ताकि बुनकरों को बैंक से आसानी से ऋण देगी। साथ ही, प्रदेश में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिये कपड़ा मंत्रालय द्वारा योजना बनायी जा रही है । उन्होने कहा कि उत्तराखण्ड में रेशम की पैदावार देश में सबसे ज्यादा है, जिसके लिये विधानसभा स्तर पर योजना बनायी जा रही हैं, जल्द ही उत्तराखण्ड के लोगों को रेशम के उद्योग से जोड़ा जायेगा। जो यहां के लोगों के लिये एक रोजगार का बड़ा साधन बनेगा वहीं यहां के परम्परागत हस्तकर्घा को भी आगे बढ़ाने के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है।

पतंजलि के प्रोडक्ट्स का उपयोग न करें मुस्लिम- दारुल उलूम

विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारूल उलूम देवबन्द के मुफ़्तियों ने योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि के गोमूत्र मिले प्रोडक्टस का इस्तेमाल को नाजायज करार दिया है, जबकि मुफ़्तियों का यह भी कहना है कि जिन प्रोडक्टस में गोमूत्र नहीं मिला है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। दारुल इफ़्ता विभाग के मुफ़्तियों का कहना है कि पतंजलि के उत्पादों में अगर गोमूत्र मिला है तो उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है, इसलिये जिन उत्पादों में गोमूत्र मिला हो या तो स्वयं कंपनी वाले इसे स्वीकार करें या किसी अन्य साधन से विश्वास या सबसे अधिक संभावना सीमा तक गोमूत्र मिश्रण का पता लग जाये तो उनका उपयोग नाजायज है। बाकी उत्पाद जिनमें गोमूत्र मिश्रित न होना नित रूप से पता हो तो उसका प्रयोग की अनुमति है। दारूल उलूम देवबंद द्वारा जारी फतवे पर देवबन्द के मुफ़्ती अरशद फारूकी ने कहा इस्लाम में गाय का पेशाब हराम व नापाक है। अगर किसी चीज में गाय का पेशाब शामिल किया जायेगा, तो वह चीज भी हराम होगी। अगर किसी कंपनी की दवाओं में गाय का पेशाब पाया जाता है तो उस दवा से भी बचना जरूरी है। ●

गेल (इंडिया) लिमिटेड

भारत की
नं.1
प्राकृतिक
गैस
कम्पनी

प्रदूषण मिटाएँ

इससे पहले कि वह मिटा दे हमारा

भविष्य

भारत में हर साल वायु प्रदूषण के कारण
14,00,000 अकाल मृत्यु हो जाती हैं।
ईंधन के तौर पर प्राकृतिक गैस को अपना कर
इस समस्या का समाधान करने में सहयोग दें।
आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करें।

#हवा बदलो

प्राकृतिक गैस अपनाएँ

PAHAL

#GiveItUp
Feel the Joy of Giving

स्रोतः इंस्टिट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्युएशन (आईएचएमई), यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन

www.changetheair.org

अर्थव्यवस्था में तेजी तो कृषि सुधारों से आएगी

वास्तविकता तो यह है कि कृषि का यह हश्र जान-बूझकर हुआ है बल्कि सारे आर्थिक सुधारों को इसी से सहारा मिला है। यदि खेती को अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिये उसका हक दिया होता तो औद्योगिक व व्यावसायिक क्षेत्रों को नतीजा भुगतना पड़ता, क्योंकि ऊंची खाद्य कीमतों के कारण मजदूरी अधिक देनी पड़ती। कृषि उपज की अधिक कीमत के कारण कई उद्योगों की लागत बढ़ जाती। कृषि में मजदूरी बढ़ती तो शहरों की ओर पलायन कम हो जाता तथा आधारभूत ढांचे व निर्माण क्षेत्र के लिए सस्ता श्रम नहीं मिलता।

■ **देविंदर शर्मा**

जरा इस पर विचार करें कि जब से आर्थिक सुधार लागू हुए हैं इन बीते 25 वर्षों में किसी दफ्तर में काम करने वाले भृत्य की औसत मासिक आधारभूत आय 7,500 रुपए से बढ़कर 18 हजार रुपए हो गई है और कैबिनेट सचिव की आय 20 हजार रुपए से बढ़कर 2.50 लाख रुपए हो गई है। हालांकि, सरकारी कमर्चारी की वेतनवृद्धि का आर्थिक उदारीकरण से कोई संबंध नहीं है, फिर भी मैं देखता हूं कि सरकारी कर्मियों की वेतनवृद्धि को आर्थिक सुधार के शानदार नतीजे के रूप में दिखाया जाता है।

अब इसकी तुलना खेती से किसान को होने वाली आमदनी से करें। 2016 का आर्थिक सर्वेक्षण हमें बताता है कि किसान को अपनी कृषि गतिविधियों से होने वाली आय देश के 17 राज्यों में 20 हजार रुपए सालाना है। इसमें वह अनाज भी शामिल है, जो वह अपने परिवार के लिए निकालकर रख लेता है। दूसरे शब्दों में इन राज्यों में किसान की मासिक आय सिर्फ 1,666 रुपए है। राष्ट्रीय स्तर पर एसएसएसओ ने किसान की मासिक आय प्रति परिवार सिर्फ तीन हजार रुपए आंकी है। निश्चित ही किसान की यह दयनीय स्थिति आर्थिक सुधारों का नतीजा है। सरल शब्दों में कहें तो आर्थिक उदारता या सुधार या बाजार अर्थव्यवस्था ने, आप जो भी नाम देना चाहें, बहुसंख्यक आबादी की अनदेखी की है। अन्य असंगठित क्षेत्रों की तरह कृषि भी इसकी सबसे बड़ी शिकार है।

जुलाई 1991 में डॉ. मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में ऐतिहासिक भाषण देकर देश की अर्थव्यवस्था को खोल दिया था। मुझे याद है कि उन्होंने उद्योगों को नियंत्रण की बेड़ियों से मुक्त किया था और उन पर रियायतों की वर्षा-सी कर दी थी और फिर अगले ही पैराग्राफ में माना था कि कृषि अब भी अर्थव्यवस्था का आधार है। किंतु कृषि राज्यों का विषय है, इसलिए उन्होंने खेती के लिए आवश्यक प्रोत्साहन का मुद्दा उन पर छोड़ दिया। यह पक्षपात साफ नज़र आया। निश्चित ही उदारीकरण का यह अनसोचा असर नहीं था बल्कि यह तो योजना का हिस्सा था। बाद में 1996 में विश्व बैंक ने भारत को निर्देश दिया कि वह अगले 20 वर्षों में 40 करोड़ लोगों को ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित करे। तर्क यह था कि भूमि बेशकीमती संपत्ति है और उसे अक्षम उत्पादकों यानी किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। चूंकि किसानों की युवा पीढ़ी को खेती के अलावा कुछ आता नहीं था, इसलिए विश्व बैंक ने सुझाव दिया कि भारत प्रशिक्षण संस्थानों का जाल बिछाए ताकि ये युवा औद्योगिक श्रमिक बन सकें। इसके साथ भूमि को किराए पर देने और उनके अधिग्रहण की शुरुआत होनी चाहिए।

एक के बाद एक आने वाली सरकारें विश्व बैंक के नुस्खे पर आंख मूंदकर चल रही हैं। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मनमोहन सिंह ने बार-बार कहा था कि भारत में 70 फीसदी किसान अतिरिक्त हैं और उन्हें शहरी क्षेत्रों में ले जाना होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन कह चुके हैं कि बड़ा सुधार तो तब होगा जब भारत खेती करने वाली आबादी के बड़े हिस्से को शहरों में बसाएगा। हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खेती को दोष दिया है कि वह आबादी के बड़े हिस्से को आजीविका न देकर विषमता बढ़ाने की दोषी है। वे यह बताना भूल गए कि सरकारों ने जान-बूझकर खेती को वित्तीय संसाधनों से वंचित रखकर कृषक समुदाय को गरीब बनाए रखा। बजट प्रावधानों में खेती को दी जाने वाली कम प्राथमिकता से यह स्पष्ट है। 11वीं योजना में खेती को पांच साल में बजट प्रावधान में सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए ही मिले। 12वीं योजना के पांच वर्षों में खेती को 1.5 लाख करोड़ रुपए मिले। संयोग से 52 फीसदी आबादी वाली खेती को मिलने वाला बजटीय समर्थन मनरेगा के वार्षिक प्रावधान से कम है। इस पर गेहूं और चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग स्थिर ही है, क्योंकि उपज मूल्य में वार्षिक वृद्धि औसतन 4 फीसदी से ऊपर नहीं जाती। आश्चर्य नहीं कि विकल्प मिलने पर 48 फीसदी किसान खेती छोड़ना चाहते हैं।

वास्तविकता तो यह है कि कृषि का यह हश्र जान-बूझकर हुआ है बल्कि सारे आर्थिक सुधारों को इसी से सहारा मिला है। यदि खेती को अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिये उसका हक दिया होता तो औद्योगिक व व्यावसायिक क्षेत्रों को नतीजा भुगतना पड़ता, क्योंकि ऊंची खाद्य कीमतों के कारण मजदूरी अधिक देनी पड़ती। कृषि उपज की

अधिक कीमत के कारण कई उद्योगों की लागत बढ़ जाती। कृषि में मजदूरी बढ़ती तो शहरों की ओर पलायन कम हो जाता तथा आधारभूत ढांचे व निर्माण क्षेत्र के लिए सस्ता श्रम नहीं मिलता। स्वामीनाथन समिति की उत्पादन लागत पर 50 फीसदी मुनाफे की सिफारिश लागू करने के प्रति उदासीनता भी इसी चिंता का नतीजा है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने लिखकर दिया है कि ऊंची कीमतें देने से बाजार अस्तव्यस्त हो जाएंगे। इसीलिए केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे समर्थन मूल्य के अलावा गेहूं व चावल पर कोई बोनस न दें। इस तरह आर्थिक सुधारों की असली लागत तो ग्रामीण भारत चुका रहा है, जिसमें बहुसंख्यक किसान हैं। पहले सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण में यह विरोधाभास साफ पता चलता है। मानव विकास सूचकांक पर भारत 188 देशों की सूची में 130वें स्थान पर है। जिन आर्थिक सुधारों की हम बात करते हैं उसमें देश की 51 फीसदी संपत्ति का फायदा 1 फीसदी धनी वर्ग को मिल रहा है। बड़े सुधारों की जरूरत तो कृषि को है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अर्थव्यवस्था को तेजी देने वाला माना जा रहा है क्योंकि इससे उपभोक्ता सामान की मांग बढ़ने की अपेक्षा है। कल्पना करें कि खेती में आमदनी बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना अधिक बढ़ावा मिलेगा। सच तो यही है कि खेती में ही अर्थव्यवस्था को तेजी देने की क्षमता है।

दुर्भाग्य यह है कि जाने-अनजाने कृषि को ही आर्थिक सुधारों के मौजूदा दौर को चलाए रखने के लिए बलिदान देने पर मजबूर किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में 60 करोड़ किसान विषमता पैदा करने वाले आर्थिक सुधारों की कीमत चुका रहे हैं। ●

खुश रहेगी गाय तो दूध होगा ज्यादा पौष्टिक

अगर आप चाहते हैं कि आप की गाय ज्यादा दूध दे और उसका दूध पौष्टिक भी रहे तो जरूरी है कि गाय स्वस्थ और खुश रहे। एक अध्ययन में यह रोचक खुलासा किया गया है कि गाय जब खुश होती है तो कहीं अधिक पौष्टिक दूध देती है और उसके दूध में कैल्शियम का स्तर अधिक होता है।

अमेरिका के विस्कॉन्सिन मेडिसन विश्वविद्यालय की शोधकर्ता लौरा हर्नांडीज के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं की टीम ने प्रसन्नता के अनुभव के लिए जिम्मेदार रसायन 'सेरोटोनिन' के सेवन का गायों के रक्त और दूध में कैल्शियम के स्तर से संबंधों की जांच की।

अनुसंधानकर्ताओं की टीम ने 24 गर्भवती गायों को एक रसायन, इंजेक्शन के जरिए दिया, जो बाद में सेरोटोनिन में परिवर्तित हो जाता है। सेरोटोनिन के कारण सभी गायों के रक्त और दूध में कैल्शियम का स्तर बढ़ गया। हालांकि सभी नस्ल की गायों में इसका असर एक जैसा नहीं रहा। हर्नाडीज ने कहा, "दो नस्लों की गायों पर किए गए इस अध्ययन में हमें पता चला कि कैल्शियम स्तर में परिवर्तन दोनों नस्लों में अलग-अलग रहा।"

शोधकर्ताओं के अलावा पशुचिकित्सक और जानकार भी पशुओं को स्वस्थ और खुश रखने की सलाह देते हैं। लखनऊ स्थित यूपी पशुपालन विभाग के डॉ. वी.के. सिंह बताते हैं, "समय से खाना, पानी मिलने से गाय खुश रहती है। इसके साथ-साथ यह बहुत जरूरी है गाय के साथ अगर आपका व्यवहार कैसा है। जितना पशु घुला-मिला रहता है उतना ही अच्छा उसका स्वास्थ्य भी रहता है, जिससे दूध का उत्पादन अच्छा होता है।"

डॉ. वी.के. सिंह आगे बताते हैं, "कई पशुपालक तो ऐसे होते हैं जो अपने पशुओं को खुश करने के लिए धीरे-धीरे आवाज में म्यूजिक चलाकर दूध निकालते हैं।"

अमेरिकी शोधकर्ताओं ने ये भी पाया कि हाल ही में बच्चे को जन्म देने वाली एक जर्सी गाय को नियमित तौर पर प्रसन्नता प्रदान करने वाला रसायन भोजन में दिया गया, तो उसके दूध में कैल्शियम का स्तर बढ़ गया। एक शोध पत्रिका 'जर्नल ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी' में प्रकाशित यह अध्ययन डेयरी कारोबारियों के लिए गायों के स्वास्थ्य में सुधार और दुग्ध उत्पादन में निरंतरता बनाए रखने में सहायक साबित हो सकता है।

वैज्ञानिकों और जानकारों की बातों से जागरूक किसान भी इत्तफाक रखते हैं। रायबरेली जिले के पशुपालक विपिन जयसवाल बताते हैं, "खाना तो सभी पशुपालक अपने पशुओं को अच्छा देते है। जरूरी यह है कि पशु आपसे प्यार करे। अगर पशु खुश है तो पास जाते ही आपका हाथ चाटेगा। उसका व्यवहार आपके प्रति बदला दिखेगा। पशु खुश रहता है तो सही से खाता है और बीमारियां भी कम होती है।"

पौष्टिक दूध और दूध के अन्य उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है। लेकिन तेजी से बढ़ती इस मांग का खामियाजा गायों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि डेयरी में पाली जाने वाली अधिकतर गायों के रक्त में कैल्शियम का स्तर कम पाया जाता है। डॉ सिंह बताते हैं, "डेयरियों के मुकाबले जिनके पास कम पशु होते हैं वे अपने पशु को ज्यादा खुश रखते हैं क्योंकि उनके पास समय होता है और हर एक पशु का ख्याल भी रखते हैं।"

जाने क्या आपकी गाय स्वस्थ और खुश है?

- अच्छे से चारा खा रही हो।
- गोबर से ज्यादा बदबू न आ रही हो।
- दूध का उत्पादन एक जैसा है।
- अपने बच्चे को अच्छे पिला रही है।
- दुहने के वक्त परेशान नहीं करती।

गाय को खुश रखने के तरीके

- समय से उनको चारा-पानी दें।
- चारे में वैरायटी लाने की कोशिश करें।
- पशुपालक को चाहिए उनके साथ समय बिताएं।
- हीट होने पर उनका गर्भाधान जरूर करवाएं।
- उन्हें साफ-सुधरी जगह पर रखें।

(साभारः kisanhelp.in)

दलहन वर्ष में थाली से गायब दाल

आमतौर पर किसान कर्ज लेकर खेती करते हैं और खेत की फसल से उनके सारे सपने जुड़े होते हैं। इसलिये वह ऐसी किसी भी खेती से परहेज करते हैं, जिसमें अधिक जोखिम उठाना पड़े। इसका परिणाम है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर में दाल की खेती में कमी दर्ज की गई है।

■ **आशीष कुमार 'अंशु'**

यह कैसा संयोग है कि वर्ष 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित करता है और दलहन की कीमत इसी साल जमीन से उठकर आसमान को छूने लगती है। वर्ष 1971 में देश में औसतन प्रति व्यक्ति को 51.1 ग्राम दाल प्रतिदिन मिल जाती था। वर्ष 2013 में औसतन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिलने वाली दाल की मात्रा घटकर 41.9 ग्राम रह गई।

यह बात चिंताजनक इसलिये भी है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दाल की मात्रा कम-से-कम 80 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होनी चाहिए थी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भोजन में दाल प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत है। इसमें गेहूं से दो गुना और चावल से तीन गुना अधिक प्रोटीन होता है।

भारत में चावल वैसे भी स्वास्थ्य मंत्रालय की चिन्ता के उस दौर से गुजर रहा है, जो डायबिटीज तक ले जाती है। वर्ष 2016 में डायबिटीज के रोग में भारत ने सीधे-सीधे चीन को टक्कर दे दी है। संभव है कि आने वाले समय में भारत डायबिटीज में चीन को पीछे ना छोड़ दें। इसकी बड़ी वजह हमारे खाने में बढ़ रहा कार्बोहाइड्रेड और कम हो रहा प्रोटीन है। वैसे इस चिन्ता को गम्भीरता से लेते हुए सरकार ने जंक फूड पर टैक्स बढ़ाने का इरादा कर लिया है। जंक फूड की देश में बढ़ रही डायबिटीज की एक बड़ी वजह के तौर पर पहचान हुई है।

भारत सरकार ने दलहन उत्पादन में वृद्धि के लिये वर्ष 2016 को दलहन उत्पादन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य विषय पर आयोजित एक परिचर्चा को सम्बोधित करते हुए दिल्ली में कहा कि दलहन उत्पादन वर्ष के दौरान किसानों को ना सिर्फ उच्च पैदावार वाली दालों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे बल्कि इससे मिट्टी में उवर्री शक्ति में वृद्धि की भी जानकारी दी जाएगी।

श्री सिंह के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक देश है और यह दुनिया में दाल की सबसे अधिक खपत वाला देश भी है। खपत अधिक होने की वजह से यहां दाल आयात करनी पड़ती है।

केन्द्र सरकार दलहन और तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये 27 राज्यों के 622 जिलों में अपनी सहायता योजना के अंतर्गत सहायता देगी।

पिछले वर्ष भारत में 31 लाख 80 हजार टन दाल आयात की गयी थी, जबकि इस वर्ष 45 लाख 90 हजार टन दाल का आयात हुई। यह आश्चर्य की बात है कि उसके बावजूद दाल की कीमत आसमान पर है। पिछले वर्ष 22 लाख हेक्टेयर में दाल की फसल लगाई गई थी। इस वर्ष 24 लाख हेक्टेयर में दाल की फसल लगाई गई है। इस वर्ष जमाखोरों के पास से सरकारी दबिश में एक लाख तीस हजार टन दाल बरामद हुई। यह सरकारी आंकड़े हैं।

एक तरफ दाल की कीमत बढ़ती जा रही है, जबकि एक अनुमान के अनुसार दाल की बढ़ती कीमतों के बावजूद किसानों की रुचि दिन-प्रतिदिन दाल की खेती में कम होती जा रही है। सिर्फ उत्तर भारत की बात करें तो यहां दाल की खेती का रकबा लगभग 25 लाख हेक्टेयर कम हुआ है। बताया जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह जोखिम है।

आमतौर पर किसान कर्ज लेकर खेती करते हैं और खेत की फसल से उनके सारे सपने जुड़े होते हैं। इसलिये वह ऐसी किसी भी खेती से परहेज करते हैं, जिसमें अधिक जोखिम उठाना पड़े। इसका परिणाम है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर में दाल की खेती में कमी दर्ज की गई है।

देश में मुख्य दलहन की फसल चना और अरहर है। ये दोनों मिलकर देश की पचास फीसदी से अधिक जरूरत पूरी कर देते हैं। इसके बाद मूंग और उड़द की दाल का नम्बर आता है। आज जब दाल आम आदमी की पहुंच से दूर हो गयी है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने आम आदमी तक दाल पहुंचाने के लिये एक सफल प्रयास किया है। जिसकी चर्चा की जानी चाहिए।

छत्तीसगढ़ सरकार प्रत्येक आदिवासी परिवार को आवश्यक प्रोटीन की पूर्ति के लिये पांच रुपए किलो के हिसाब से दस रुपए में दो किलो चना प्रत्येक महीने उपलब्ध करा रही है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 48 हजार क्विंटल चने का वितरण प्रत्येक महीने हो रहा है। इसी प्रकार गैर आदिवासियों

को दो किलो दाल बीस रुपए में उपलब्ध कराई जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इस प्रकार सरकार ने पोषण कार्यक्रम से जोड़कर पूरे देश के लिये एक मिसाल कायम की है।

बीते तीन-चार दशकों में जहां देश में आबादी बढ़ने से दाल की मांग बढ़ी है, दूसरी तरफ घरेलू पैदावार में हम उसके मुकाबले दलहन का उत्पादन बढ़ाने में असफल रहे हैं। दक्षिण भारत में दलहन की बढ़ी खेती हमें थोड़ा आशान्वित जरूर करती है लेकिन उत्तरी भारत में लगातार दलहन की खेती की बढ़ती उपेक्षा निराश भी करती है।

गौरतलब है कि दक्षिण भारत में दलहन की खेती कम पानी में और बंजर-असिंचित भूमि में की जा रही है। यदि दक्षिण भारत के किसानों को विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और थोड़ी सी सरकारी सहायता मिले तो वहां दाल का उत्पादन बढ़ सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिये केन्द्र सरकार ने दलहन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष बजट का प्रावधान किया है।

बजट के साथ-साथ विशेषज्ञों की टीम की देखरेख में दलहन की खेती को पूर्वोत्तर भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देश के 27 राज्यों के 623 जिलों के 474 कृषि विकास केन्द्रों को दलहन की खेती अभियान के क्रियान्वयन से जोड़ने के साथ-साथ उनके लिये लक्ष्य भी निर्धारित किया जाना चाहिए।

पूरी दुनिया के देश अपने यहां दाल के इस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में दाल उत्पादन को बढ़ाने की अलग-अलग योजनाएं बना रहे हैं। उम्मीद है अगले साल भारत में बनी योजनाओं का परिणाम देख पूरा देश खुश होगा और अगले वर्ष दाल इतनी महंगी नहीं होगी कि आम आदमी की थाली से दाल की कटोरी फिर गायब हो जाये। ●

हरित क्रांति के पुरोधा डॉ. स्वामीनाथन

■ कृषि चौपाल

स्वामीनाथन वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। वर्ष 1999 में टाइम पत्रिका ने स्वामीनाथन को 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई व्यक्तियों में से एक बताया था।

आनुवांशिकी वैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925, कुंभकोणम, तमिलनाडु में हुआ। उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विख्यात हैं। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज गरीब किसानों के खेतों में लगाए गए थे। इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न की सर्वाधिक कमी वाले देश के कलंक से उबारकर 25 वर्ष से कम समय में आत्मनिर्भर बना दिया था। उस समय से भारत के कृषि पुनर्जागरण ने स्वामीनाथन को कृषि क्रांति आंदोलन के वैज्ञानिक नेता के रूप में ख्याति दिलाई। स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्मभूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

भारत गांवों का देश है और यहां की अधिकांश जनता कृषि के साथ जुड़ी हुई है। इसके बावजूद अनेक वर्षों तक यहां कृषि से संबंधित जनता भी भुखमरी के कगार पर अपना जीवन बिताती रही। इसका कारण कुछ भी हो, पर यह भी सत्य है कि ब्रिटिश शासनकाल में भी खेती अथवा मजदूरी से जुड़े हुए अनेक लोगों को बड़ी कठिनाई से खाना प्राप्त होता था। कई अकाल भी पड़ चुके थे। भारत के संबंध में यह भावना बन चुकी थी कि कृषि से जुड़े होने के बावजूद भारत के लिए

भुखमरी से निजात पाना कठिन है। इसका कारण यही था कि भारत में कृषि के सदियों से चले आ रहे उपकरण और बीजों का प्रयोग होता रहा था। फसलों की की उन्नति और बीजों में सुधार की ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। स्वामीनाथन ही वे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने सबसे पहले गेहूं की एक बेहतरीन किस्म को पहचाना। इसके द्वारा भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता था। यह मैक्सिकन गेहूं की एक किस्म थी, जिसे स्वामीनाथन ने भारतीय खाद्यान्न की कमी दूर करने के लिए सबसे पहले अपनाने के लिए स्वीकार किया। इसके कारण भारत के गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई।

लंदन की रॉयल सोसायटी सहित विश्व की 14 प्रमुख विज्ञान परिषदों ने एम. एस. स्वामीनाथन को अपना मानद सदस्य चुना है। अनेक विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया है। विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों के साथ प्राप्त धनराशि से एम. एस. स्वामीनाथन ने वर्ष 1990 के दशक के आरंभ में अवलंबनीय कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए चेन्नई में एक शोध केंद्र स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का मुख्य उदेश्य भारतीय गांवों में प्रकृति तथा महिलाओं के अनुकूल प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार पर आधारित रोजगार उपलब्ध कराने वाली आर्थिक विकास की रणनीति को बढ़ावा देना है। फाउंडेशन में पर्यावरण प्रौद्यौगिकी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। स्वामीनाथन दक्षिण एशिया के उत्तरदायित्व के साथ पर्यावरण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यूनेस्को में भी पदासीन रहे हैं। उनकी महान विद्वता को स्वीकारते हुए इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी और बांग्लादेश, चीन, इटली, स्वीडन, अमेरिका तथा सोवियत संघ की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों में उन्हें शामिल किया गया है। वह वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। 1999 में टाइम पत्रिका ने स्वामीनाथन को 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई व्यक्तियों में से एक बताया था। ●

हरियाणा को दूध उत्पादन में नंबर-1 बनाना है-धनखड़

हरियाणा के कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ से पिछले दिनों चंडीगढ़ में उनके आवास पर मुलाकात हुई। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और इस बीच उनसे हरियाणा में कृषि की दशा और दिशा पर लंबी बातचीत हुई। कर्मठ और जुझारू नेता धनखड़ खेती को लाभ का धंधा बनाने के प्रति प्रतिबद्ध दिखे। उन्होंने बताया कि मौसमी फसलों से साथ वे किसानों को बागवानी के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। जहां वे दिल्ली की चार करोड़ आबादी को फल-फूल, सब्जी सहित अन्य रोजमर्रा की चीजें मुहैया कर हरियाणा के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं, वहीं उनका सपना हरियाणा को दूध उत्पादन में नंबर एक पर लाना है। ऐसा वे कैसे करेंगे, उनके पास ऐसी कौन-सी योजनाएं हैं, इस मुद्दे पर उनसे 'कृषि चौपाल' के संपादक महेन्द्र बोरा और ललित पांडे की लंबी बातचीत हुई।

● आप हरियाणा के किसानों का आर्थिक स्तर ऊपर उठाने के प्रति प्रतिबद्ध नजर आते हैं?

हमारा लक्ष्य ग्रामीण कृषि को बढ़ावा देना है। दिल्ली और उसके आसपास करीब चार करोड़ की आबादी रहती है, हम उनके लिए खेती करना चाहते हैं। हम दिल्ली वालों को फल-फूल, सब्जी, दूध, मछली और अंडा-चिकन आदि सप्लाई करना चाहते हैं। इस सिलसिले में हमारी केंद्र सरकार से दो बार बातचीत हो गई है। इससे हरियाणा के किसानों की आमदनी बढ़ेगी। बागवानी को भी बढ़ावा देना हमारा लक्ष्य है। वतर्मान में हरियाणा में मात्र सात फीसदी क्षेत्र में बागवानी होती है, इसे हम बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक ले जाना चाहते हैं। हरियाणा में अभी 4.52 लाख हेक्टेयर में बागवानी की जाती है और कुल उत्पादन करीब 25.1 लाख टन है, जबकि हमने बागवानी का क्षेत्रफल बढ़ाकर 9 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कुल उत्पादन 270 लाख टन पहुंचने की उम्मीद है।

● इसके लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं?

बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य के हर जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस और फूलों की मंडी बनाने की हमारी प्राथमिक योजना है। सोनीपत के गन्नौर में 600 एकड़ में मंडी प्रस्तावित है, जिस पर तेजी से काम हो रहा है। हरियाणा में 108 मंडियां हैं, जिसमें से 54 को हम ई-मंडी बना रहे हैं। अभी चार मंडियां शुरू हो चुकी हैं और 2017 तक बाकी भी काम करने लगेंगी। फॉर्म जे (किसानों को मंडी से मिलने वाला पत्र) के जरिए हर साल 12 करोड़ रुपये के ईनाम किसानों को दिए जा रहे हैं, जिसके तहत टैक्टर, मोटर साइकिल व कम्प्यूटर दिए जाते हैं। ऐसी योजनाओं से किसानों का रुझान बागवानी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जब हम उन्हें बाजार उपलब्ध कराएंगे और उनके द्वारा उत्पादित माल की ब्रांडिंग भी करेंगे, तो कुछ ही सालों में बागवानी की फसलों से हरियाणा के किसानों की आय दस गुना तक बढ़ जाएगी।

● आप दूध उत्पादन में काफी जोर दे रहे हैं?

दूध उत्पादन में हमारा लक्ष्य नंबर-1 पर आना है। वतर्मान में हम तीसरे नंबर पर हैं, गुजरात पहले और पंजाब दूसरे नंबर पर है। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हम हर साल किसानों के बीच छह करोड़ रुपये के ईनाम बांट रहे हैं और प्रति लीटर दूध पर पांच रुपये प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। देसी गाय के दूध की विशेष ए-2 क्वालिटी को अलग से बेच रहे हैं, जो 70 रुपये प्रति लीटर है। देसी गाय की खरीद पर दस से बीस हजार रुपये सब्सिडी दी जा रही है। इसके दूध को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता भी कराई जा रही है। राज्यभर में 117 गायों को ईनाम दिया गया, जिसमें चार नस्लों को ढ़ाई-ढ़ाई लाख रुपये दिए गए।

● क्या आप बेमौसमी सब्जियों को भी बढ़ावा दे रहे हैं?

इजराइल से हम दूध और बागवानी दोनों क्षेत्रों में सहयोग ले रहे हैं। उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर कृषि और फल उत्पादन में किया जाये, तो उसका सीधा लाभ हरियाणा के किसानों को मिलेगा। हमारी सभी नीतियां किसानों और आम लोगों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। इनके आर्थिक जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं।

● आप इतनी योजनाएं ला रहे हैं, फिर अन्य राज्यों की तरह हरियाणा में भी किसानों की आत्महत्या की घटनाएं आम क्यों हैं?

हरियाणा में किसान आत्महत्या नहीं करते। यहां का किसान बहुत मेहनती हैं। पिछली सरकारों ने किसानों के साथ छल किया था, लेकिन हमारी सरकार उन्हें समृद्ध बनाना चाहती है।

● किसानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बैंक उन्हें आसानी से कर्ज नहीं देते। अगर

बैंक किसानों को कर्ज देते भी हैं, तो उगाही में वे उन्हें बहुत परेशान करते हैं, जबकि माल्या जैसों के साथ बैंक समझौते करते हैं?

हरियाणा में किसानों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बैंक उन्हें कर्ज देते हैं और किसान क्रेडिट कार्ड पर जीरो परसेंट पर कर्ज देते हैं। कुछ किसान, जो बैंकों का कर्ज नहीं चुकाते, उनकी वजह से सारे किसानों को बदमान नहीं किया जाना चाहिए।

● हरियाणा सरकार ने केंद्र से कहा कि पिछले साल बारिश कम हुई, लेकिन राज्य में सूखा नहीं है। क्या इसके बाद भी आपने मुआवजा बांटा?

किसानों को मुआवजा दिया गया है, लेकिन वह सफेद मक्खी के कारण खराब हुई फसल पर 1092 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया। सफेद मक्खी का कोई इलाज नहीं है। 15 वर्षों में इनेलो व कांग्रेस की सरकारों ने किसानों को मुआवजे के रूप में केवल 1,500 करोड़ रुपए दिए, जबकि हमारी सरकार ने मात्र डेढ़ साल में प्रदेश के किसानों को मुआवजे के रूप में 2200 करोड़ रुपए दिए हैं।

● पानी की कमी की वजह से कई राज्यों में किसानों से धान न बोने की अपील की जा रही है, क्या आपने भी कोई ऐसी अपील की है?

मौसम की वजह से खेती का ट्रेंड बदल रहा है, इसलिए कई राज्यों ने ऐसी अपील की है, जोकि सही है। कई जगह आर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये वहां की जरूरत है। अभी हमने किसानों से ऐसी कोई अपील नहीं की है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम भी ऐसा करेंगे।

● प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर आप पदयात्रा कर रहे हैं, इस योजना की हरियाणा में वतर्मान स्थिति क्या है?

राज्य के किसान बढ़-चढ़कर इस योजना का लाभ ले रहे हैं। खरीफ की चार फसलों- बाजरा, धान, कपास और मक्का में यह योजना लागू की गई है। धान की फसल के लिए 25,000 प्रति एकड़ के लिए किसान को 500 रुपये, कपास के लिए 24,480 प्रति एकड़ के लिए 480 रुपये, बाजरे के लिए 11,000 प्रति एकड़ के लिए 220 रुपये तथा मक्का के लिए 10,000 प्रति एकड़ के लिए 200 रुपये प्रीमियम के रूप में देने होंगे। किसान को किसी भी फसल के लिए दो प्रतिशत से अधिक प्रीमियम नहीं देना है। जो किसान ठेके या बटाई पर खेती कर रहे हैं, उन्हें भी बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है, उन्हें सिर्फ भू-मालिक से एक स्व-हस्ताक्षरित पत्र जमा करवाना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले एक-दो साल में हरियाणा देश का पहला राज्य होगा, जो इस क्षेत्र में पूरी तरह जोखिम मुक्त होगा। ज्यादा से ज्यादा किसान इस बीमा योजना का लाभ लें, इसके लिए मैं 21 जुलाई को गांव दुल्हेड़ा से जिला झज्जर मुख्यालय तक 13 किलोमीटर तक पैदल यात्रा कर रहा हूं। (यह साक्षात्कार यात्रा से पहले लिया गया था) जिस प्रकार एक अभिनेता अपनी फिल्म का प्रचार करता है, उसी तरह एक कृषि मंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री फसल बीमा का प्रचार करना मेरी पदयात्रा का उद्देश्य है। ●

दूध उत्पादन में हमारा लक्ष्य नंबर-1 पर आना है। वतर्मान में हम तीसरे नंबर पर हैं, गुजरात पहले और पंजाब दूसरे नंबर पर है। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हम हर साल किसानों के बीच छह करोड़ रुपये के ईनाम बांट रहे हैं और प्रति लीटर दूध पर पांच रुपये प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं।

किसानों के रडार पर मोदी सरकार

मोदी सरकार को पांच साल निकालने हैं, जिसमें से दो-ढाई साल ये निकाल चुके हैं, इसलिए बाकी बचे समय को ये सब्जबाग दिखाकर निकालना चाहते हैं। किसान इनके रडार में नहीं हैं, बल्कि ये किसानों के रडार पर आ गए हैं। किसानों की जान जा रही है, लेकिन इनके शासन में बनियों की पौ-बारह है।

महेंद्र सिंह माहरा, सांसद, कांग्रेस

भाजपा सरकार की कथनी और करनी में जमीन-आसमान का अंतर है। सरकार कहती क्या है और करती क्या है, यह जगजाहिर हो चुका है। ये लोग पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। जहां तक सरकार का यह दावा है कि वह 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देगी, तो यह बिल्कुल असंभव है। मैं यह बात यूं ही नहीं कह रहा हूं। आप देखिए न कि किसानों तक सरकारी विभागों की पहुंच कितनी है? सरकारी विभागों की किसानों और आम आदमी तक पहुंच ही नहीं है, तो उनकी आय दोगुनी करने का दावा महज छलावा भर है। हम संसद की ग्रामीण विकास कमेटी के दौरे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकंपा) के अध्यक्ष शरद पवार जी के क्षेत्र पुणे (बारामती) गए थे, वहां हमने जो देखा, वह आश्चर्य में डालने वाला था। वहां अपना एक अलग ही सिस्टम था। वहां कृषि से संबंधित बड़े अधिकारी भले न हों, लेकिन विभाग के कर्मचारी जरूर थे। वे किसानों को कृषि से संबंधित पूरी जानकारी दे रहे थे। इससे किसानों को एक संदेश मिलता है और वे उत्साहित होकर कृषि कार्य करते हैं, जिसके निश्चित तौर पर सुखद परिणाम आते हैं। केंद्र सरकार की किसानों तक कोई पहुंच ही नहीं है, तो वह किसानों का क्या भला कर पाएगी?

सवाल यही है कि केंद्र सरकार कैसे किसानों को लाभ देगी? न तो हमारे पास ऐसे बीज हैं, जो भरपूर फसल दें और न ही जमीन की उर्वरता को बढ़ाने एवं पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं। गेहूं-धान के बीज को नया बना दें, ऐसे वैज्ञानिक हमारे पास हैं ही कहां? यूं भी खेती-किसानी में एक-दो समस्याएं तो हैं नहीं, बल्कि नकली बीज, नकली खाद और नकली कीटनाशकों से बाजार अटा पड़ा है, तो ज्यादातर जगहों में जंगली जानवरों व बंदर फसलों को चौपट कर रहे हैं।

दरअसल, सरकार के पास ये बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि पिछले दो साल में उसने क्या किया, इसलिए वह अगले दो सालों के सपने दिखाने लग गई है। सरकार की असफलता पर संसद में प्रश्न उठता रहता है, लेकिन सरकार ने उसका उत्तर देना तक मुनासिब नहीं समझा, तब इस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। हर देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री संसद में मौजूद होने के बावजूद कुछ नहीं बोलते। हमारे प्रधानमंत्री मात्र दस-पंद्रह मिनट संसद में बैठकर चले जाते हैं, बाकी समय में वे विदेश यात्राओं पर होते हैं। ऐसे में, उन्हें किसानों की सुध कहां है? जब मुखिया का ऐसा व्यवहार है, तब आगे क्या बात करें। वह तो हमारे सांसद खेत से जुड़े होते हैं, इसलिए वे संसद में किसानों से जुड़े सवाल पूछ लेते हैं वरना इन्हें किसानों पर चर्चा करने की फुर्सत तक नहीं है।

योजनाएं बना देने भर से कुछ नहीं होता है। यूं भी ज्यादातर योजनाएं पुरानी बोतल में नई शराब जैसी हैं। ये सरकार जितने बिल ला रही है, वे सभी पिछली सरकार के समय के हैं। इन बिलों पर तब ये हमारा विरोध करते थे, संसद नहीं चलने देते थे और अब वही बिल पेश कर रहे हैं। मैं ज्यादा क्या बताऊं, इन्होंने आस्ट्रेलिया से जो दाल मंगाई है, हमारे बगल में बैठे इनके ही सांसद कहते हैं कि ये दाल बहुत खराब है, खाने लायक नहीं है। इन्हें पांच साल निकालने हैं, जिसमें से दो-ढाई साल ये निकाल चुके हैं, इसलिए बाकी बचे समय को ये सब्जबाग दिखाकर निकालना चाहते हैं। किसान इनके रडार में नहीं हैं, बल्कि ये किसानों के रडार पर आ गए हैं। किसानों की जान जा रही है, लेकिन इनके शासन में बनियों की पौ-बारह है। दो साल में इन्होंने कितने बनियों के गोदामों में छापा मारा? इस बारे में कुछ भी पूछो, तो ये अपनी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल देते हैं। इन्होंने दो साल में कुछ भी नहीं सीखा और बात कांग्रेस के साठ साल की करते हैं। आम लोगों की निराशा को देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज चुनाव हो जाएं, तो इनका पर्दाफाश हो जाएगा। देश के गरीब तबके के पास दो वक्त की रोटी तक नहीं है।

मैं यह मानता हूं कि चुनाव के दौरान सत्ता विरोधी लहर थी और कांग्रेस का ग्राफ भी गिरा था, लेकिन उस वक्त खाद्य वस्तुओं की इतनी दिक्कत नहीं थी, जितनी अभी है। ऐसा जान-बूझकर किया जा रहा है, ताकि बनियों को फायदा पहुंचे। चुनाव में बनियों ने इन्हें पैसा दिया, वे अब उसे वसूलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सारा माल अपने गोदामों में जमा कर रखा है, जिससे महंगाई बढ़ रही है। मामला कुछ ऐसा हो गया है कि आज मैं संसद में कोई संवेदनशील मुद्दा उठाता हूं और इन्हें लगता है कि ये मुद्दा तूल पकड़ सकता है, तो ये अगले दिन कोई दूसरी चीज पैदा कर देते हैं, जिससे लोगों का ध्यान असल मुद्दे से हट जाए।

वैसे मैं यह नहीं कह रहा हूं कि किसानों की आय दोगुनी नहीं की जा सकती, लेकिन इसके लिए इच्छाशक्ति की जरूरत होती है, जो कि इस सरकार के पास नहीं है। कृषि में राज्यों की इक्का-दुक्का, जबकि ज्यादातर केंद्र की ही योजनाएं होती हैं। ऐसे में ये बताएं कि इनके पास किसानों की आय बढ़ाने के विकल्प क्या हैं? कृषि के परंपरागत तरीके से यह संभव नहीं है। ये सरकार किसानों और आम आदमी के प्रति कितनी गंभीर है, इसका पता इसी से चल जाता है कि इन्होंने उत्तराखंड का पैसा रोक रखा है, जबकि वहां इतनी बड़ी आपदा आई और उससे पहले जंगल आग की चपेट में आ गए थे। सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। वे रात में दो बजे सोते हैं, तो सुबह आठ बजे आफिस में होते हैं। ये संदेश गांव-गांव तक पहुंच रहा है कि हरीश रावत काम करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनके खिलाफ है। ●

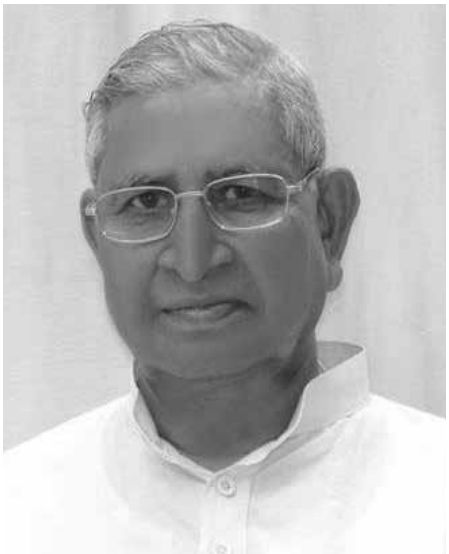

सरकार किसानों की आय दोगुना करने की सोच रही है

मेघराज जैन, सांसद, भाजपा

इसका विश्लेषण करना होगा कि किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? ये सब देखने और समझने वाली बातें हैं कि किसानों ने ऋण कहां से लिया और कितना लिया, उसका उपयोग कहां किया। सरकार मुआवजे के रूप में उन्हें सहयोग करती है, लेकिन इससे पूरी भरपाई नहीं हो पाती। किसानों को किसी भी हाल में आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। उन्हें संघर्ष का माद्दा रखना चाहिए कि कर्ज लिया है, तो उसे किसी तरह चुकाएंगे। हम सभी राजनीतिक दल बारी-बारी से किसान की आत्महत्या पर हल्ला मचाते हैं। किसान की माली हालत खराब हो तो हल्ला और अनाज के दाम नहीं मिल रहे तो हल्ला। सबसे ज्यादा हल्ला संसद में होता है, इसके अलावा किसान संगठन सड़कों पर उतर आते हैं।

किसान की वास्तविक हालात से किसी को मतलब नहीं, सभी को अपनी नेतागीरी-राजनीति की पड़ी रहती है। किसान की उपज का दाम बढ़ता है, तो महंगाई का हल्ला जोर-शोर से होने लगता है। बरसात के दिन हैं, तो जाहिर तौर पर सब्जियां वगैरह कम होंगी। इस व्यावहारिकता के बारे में कोई नहीं सोचता। सभी सरकार और बिचौलियों को कोसने लगते हैं। किसान को वाजिब दाम कब मिलेंगे? आप किसी से भी पूछो कि उसके घर में सबसे कम खर्च किसका है, तो उसका जवाब रसोई घर होगा, जोकि सीधे किसान से जुड़ा है। हर आदमी चाहे वह नेता, पत्रकार, सेठ कोई भी हो, उसे खाने की चीजें सस्ती चाहिए। वे पेन, जूते, घड़ी, गाड़ी अन्य तमाम चीजें महंगी से महंगी खरीदेंगे, लेकिन खाना सस्ता चाहिए। लोगों में मुकाबला होता है कि किसका फोन कितना महंगा है। इसी तरह पेट्रोल का दाम सौ रुपये लीटर कर दो, तो लोगों के घूमने-फिरने में कोई फर्क नहीं आएगा। वे 50-80 किलोमीटर तक अपनी कार से अपना मनपसंद खाना खाने जाएंगे। वहां होटल वाला जितना बिल देगा, उसे चुकाएंगे, ऊपर से टिप भी देंगे। दूसरी ओर दाल, सब्जी इत्यादि के थोड़ा दाम भी बढ़ेंगे, तो यही लोग हल्ला मचाने लगते हैं। आखिर किसान कहां जाएगा? उसका भी घर-परिवार है। अन्य सामानों की तरह किसान के अनाज की भी लागत मूल्य निकालकर उसका दाम तय होना चाहिए। इसका एक कारण किसानों का संगठित न होना है। किसानों के संगठन हैं, लेकिन उनका काम सरकार के खिलाफ आवाज उठाने भर का है।

दूसरी ओर किसान भी परंपरागत खेती को छोड़कर नए तरीकों को अपनाने में हिचकिचाते हैं। एक साल किसी चीज के दाम बढ़ जाएं, तो अगले साल सारे किसान वही फसल बोने लगते हैं। ऐसे में, भरपूर फसल होने से उस अनाज के दाम कम हो जाते हैं। इस बात को न किसान समझने को तैयार हैं और न ही उपभोक्ता। इसमें किसानों का दोष कम है और उपभोक्ता का ज्यादा। किसानों की उपज पर उपभोक्ताओं को ज्यादा दाम चुकाने की आदत डालनी चाहिए। किसान किस कठिनाई में खेती करता है, इसके बारे में उपभोक्ता सोचने-जानने को तैयार नहीं हैं। घड़ियाली आंसू बहाना हर किसी का धंधा बन गया है। सर्दी-बरसात, गर्मी-जाड़ा, रात-दिन हर वक्त किसान व उसके परिवार को खेती में लगाना पड़ता है। प्रकृति मेहरबान हुई, तब जाकर किसान के घर अनाज आता है। इसके बाद उसे बाजार में अपनी फसल के सही दाम मिल गए तो ठीक, नहीं तो निराश-हताश होकर वे आत्महत्या कर लेते हैं। आज हालात ये हैं कि किसान का बेटा खेती की बजाय दो हजार रुपये की नौकरी करना पसंद कर रहा है। किसान ने खेती करना छोड़ दिया, तो रोटी तक नहीं मिलेगी। आज रोटी मिल रही है, तो उसे खाकर लोगबाग चिल्ला रहे हैं।

किसान को इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? किसी कंपनी में कोई व्यक्ति नौकरी करता है, तो उसे तनख्वाह मिलती है। वहां ओवर टाइम के भी पैसे मिलते हैं, लेकिन किसान को कुछ भी नहीं मिलता है, जबकि उसका पूरा परिवार दिन-रात खेती में जुटा रहता है। कंपनी में माल बनता है तो उसका सारा खर्च जोड़कर बाजार में बेचा जाता है, लेकिन किसान की फसल के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर किसान की मेहनत और उसके फसल की पूरी लागत निकाली जाए तो सबकी आंखें खुली रह जाएंगी।

ऐसे हालात में भी हमारी सरकार किसानों की आय दोगुना करने की सोच रही है, इसलिए इस बार का बजट पूरी तरह कृषि आधारित रखा गया। देश में 60 प्रतिशत किसान हैं और किसानों की जेब में पैसा आए, मोदी सरकार इसी ओर प्रयास कर रही है। कांग्रेस को कोई सवाल पूछने से पहले ये बताना चाहिए कि उसने साठ सालों तक क्या किया। केंद्र सरकार योजनाएं जरूर बनाती है, लेकिन उन्हें क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राज्यों की होती है। योजना को फलीभूत होने में समय लगता है। एक-दो साल में यह संभव नहीं होता। मोदीजी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने ऐसी कई योजनाएं बनाई हैं, जिससे किसानों के वैकल्पिक आय के साधन बढ़ें, उन्हें समय पर सही बीज, खाद, कीटनाशक प्राप्त हों, उनकी फसल का बीमा करवाया है और किसान इसका लाभ भी उठा रहे हैं।

वैसे केवल सरकार के सोचने से किसानों का कायापलट नहीं होगा, बल्कि स्वयं किसानों को भी इस ओर पहल करनी होगी। अभी हालात ऐसे हैं कि किसान किसी दुकानदार से रोजमर्रा का सामान उधार ले आता है। उसे बीच में नकद पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वह उसी दुकानदार से ले लेता है। फसल बेचकर जब वह दुकानदार का कर्ज चुकाता है, तो उसकी हालत पहले जैसी ही हो जाती है। पहले किसान-गाय, किसान-बैल की जोड़ी हुआ करती थी, यह परंपरा थी, लेकिन आज ये उपलब्ध नहीं है। गाय पालने पर किसान को कोई खर्चा नहीं करना होता, बल्कि उसका गोबर-मूत्र से वह खेत के लिए खाद तैयार कर सकता है, जबकि उसे पांच-छह लीटर रोज दूध मिलेगा। कुछ दूध का उपयोग स्वयं करके बाकी को वह बेच सकता है, जिससे उसे मासिक आय होगी। यह आय उसके लिए वैकल्पिक होगी, जिससे वह रोजमर्रा का समान खरीद सकता है। फसल से मिली रकम उसकी जेब में आएगी। तभी वह अन्नदाता की उपाधि को भी सार्थक कर सकता है। ●

बाढ़ से बेहाल जीवन

जून से अगस्त तक आधे से ज्यादा भारत बारिश के पानी में जलमग्न रहा और सरकारों के तमाम दावे आसमान में छू मंतर हो गए। बाढ़ सैकड़ों जिंदगियों को लील गई तो लाखों लोग इससे त्रस्त रहे, जबकि लाखों एकड़ में बोई गई फसलें बर्बाद हो गईं। बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन यदि सरकार और समाज अब भी न चेते तो सूखा और बाढ़ को भारत की नियति बनते देर नहीं लगेगी।

■ **ललित पांडे**

केन्द्र और राज्य सरकारों ने खम ठोंककर दावा किया था कि वह आने वाले महीनों में होने वाली बारिश के पानी से बचाव व उसके संरक्षण के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन मौसम की पहली बारिश ने ही उनके तमाम दावों की पोल खोल दी। तमाम राज्यों में राजधानी तक की सड़कें पानी से लबालब भर गईं, जबकि कस्बों और गांवों में लोगों ने अपने लिए सुरक्षित जगहों की खोज शुरू कर दी। इसके बाद जब बारिश बढ़ती गई तो पूरा देश जलमग्न हो गया और सरकारी दावे आसमान में छू मंतर हो गए।

जून-जुलाई से लेकर सितंबर तक लगभग आधा भारत बाढ़ की चपेट में रहा। इस बीच बाढ़ सैकड़ों जिंदगियों को लील गई तो लाखों लोग इससे त्रस्त रहे, जबकि लाखों एकड़ खेत पानी में डूब गए और फसलें बर्बाद हो गईं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, गुजरात में बाढ़ ने भयंकर भारी तबाही मचाई तो राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों भी में जन-जीवन अस्त-व्यस्थ हो गया। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से राजधानी पटना तक में बाढ का खतरा मंडराने लगा। पटना में पिछले 22 साल का रिकॉर्ड टूट गया और 1975 के बाद यह पहला मौका था जब शहर के रिहायशी इलाकों तक में बाढ़ का पानी घुस गया। गंगा नदी के किनारे बसे कस्बों-गांवों में सरकारी चेतावनियां तक जारी की गईं। राज्य की कई अन्य प्रमुख नदियां भी विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बहीं। रोहतास में सोन नदी में आए उफान का असर कई इलाकों में देखने को मिला। डेहरी क्षेत्र में दूध के एक प्लांट में बाढ़ का पानी इस कदर प्रवेश कर गया कि उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया।

उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहीं। इलाहाबाद में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां खतरे के निशान को पार कर गईं और जबरदस्त तबाही मचाई। दोनों नदियों में आई बाढ़ ने एक चौथाई शहर और तकरीबन डेढ़ सौ गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। चित्रकूट में मंदाकिनी का जलस्तर चिंताजनक रहा तो बांदा में केन नदी खतरे के निशान से ऊपर बही और दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट कई सप्ताह तक रहे। इसके अलावा बलिया, सोनभद्र, गाजीपुर और महोबा जैसे जिलों में बाढ़ का कहर लगातार जारी रहा। इसमें महोबा का सबसे बुरा हाल रहा, जहां 35 साल बाद ऐसी बाढ़ आई कि यहां पर लगभग आधा दर्जन तालाब लबालब हो गए। सूबे में सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति बुंदेलखंड की रही। सूखे के बाद अब बाढ़ से जूझते बुंदेलखंड की हालत ये है कि पिछले दो वर्षों में लगातार चार फसलें या तो

बोई नही जा सकीं या मौसम के दुष्चक्र के कारण बुरी तरह खराब हो गईं। पहले भीषण सूखे की मार ने बुंदेलखंड के किसानों को मारा, अब जल के जलजले ने बचा हुआ काम कर दिया। इस बाढ़ में बड़ी मात्रा में फसलों का नुकसान हुआ है।

राजस्थान के भी कई जिलों में बाढ़ ने ऐसा तांडव दिखाया कि कइयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि खेतों का नक्शा ही बदल गया। धौलपुर, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़ सहित कई जिले के हजारों गांव में जिंदगी बाढ़ में ऊनफती नजर आई और फसल पूरी तरह चौपट हो गई। राज्य के कई इलाकों में हालात इतने असमान्य हो गए कि वहां सेना तक बुलानी पड़ी।

मध्य प्रदेश में भी हालात कमोवेश ऐसे ही थे। नदी किनारे बसे शहरों-कस्बों-गांवों की बात छोड़ दें तो राजधानी भोपाल तक में लोगों के घरों में पानी घुस आया। शहर में जीवन कई सप्ताह तक अस्त-व्यस्थ रहा। छतरपुर, पन्ना, दमोह, इटारसी, बैतूल, हौशंगाबाद, रायसेन, टीकमगढ़, रीवा, सतना, जबलपुर, रतलाम, मंदसौर, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, धार, गुना सहित कई जिलों में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई। इस बाढ़ में हजारों लोग फंस गए और बाद में सेना की मदद से उन्हें निकाला गया। मौसम विभाग के मुताबिक, जून से अगस्त तक हुई बारिश में मध्य प्रदेश के तीस जिलों में सामान्य से अधिक, 18 जिलों में सामान्य और तीन जिलों में कम वर्षा दर्ज की गई। इसी तरह गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल सहित कई राज्यों बारिश के

पानी ने जमकर कहर बरपाया। कहीं बाढ़ लोगों को बहा ले गया, कहीं सड़क, कहीं पहाड़ और फसल, वह पूरी तरह बर्बाद हो गई। पहले से ही सालों के सूखे से त्रस्त किसानों को इस मॉनसून का बेसब्री से इंतजार था। मॉनसून आया भी, लेकिन राहत देने की बजाए उसने उनकी जिंदगी को ही तबाह कर दिया।

अभी सरकारों ने कहां कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन शुरू ही किया है, लेकिन बाढ़ और इससे हुए नुकसान को लेकर राजनेताओं के बीच नुराकुश्ती शुरू हो गई है। हर नेता अपने आपको आम आदमी और किसान का हितैषी बता रहा है, फिर चाहे वह विपक्ष में हो या सत्ता में।

खैर, नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का यह खेल पुराना है, लेकिन यह बात तय है कि बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई अब संभव नहीं दिखती है। हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी कि इस बार मॉनसून जल्दी आएगा और काफी प्रभावशाली भी होगा। तब सरकारों ने दावा किया था कि वे बारिश के पानी को सहेजने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन अंत में ढाक के तीन पात वाली कहावत ही चरितार्थ हुई। बहरहाल, जब सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान पहले ही लग गया था, तब पानी के प्रबंधन को लेकर ठोस कवायद करने की जरूरत थी। लेकिन, अब वक्त आ गया है कि भारत में जल प्रबंधन को अनियमित और फौरी तौर-तरीकों से निजात दिलाई जाए और एक दूरगामी नीति के तहत काम किया जाए। पिछले कई वर्षों से भारत के तमाम ग्रामीण इलाकों के अलावा कई महानगर बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इसी के साथ-साथ जल संकट भी बढ़ रहा है। अब भी अगर सरकार और समाज ने गंभीरता से उपाय नहीं किए तो बाढ़ और सूखा देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा बोझ बन जाएंगे। दुनिया में मौसम का चक्र जिस तरह से बदल रहा है, उसके रहते जल प्रबंधन को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर इसके तहत दूरगामी नीतियां बनानी होंगी। सभी बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को इसका हिस्सा बनाना होगा। इसके लिए केंद्र और राज्यों में समन्वय होना चाहिए, साथ ही एक सक्षम आपदा प्रबंधन तंत्र भी विकसित किया जाना चाहिए। प्रकृति के मिजाज को पहचानकर उसके साथ जीने की कला हमें नए सिरे से सीखने की जरूरत है। ●

खाद्य तेल के लिए तोरिया उत्पादन

तोरिया के सफल उत्पादन हेतु शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त मानी गयी है। इसे 20-40 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सुगमता से उगाया जा सकता है। भारत में इसे रबी मौसम में उगाया जाता है। इसकी खेती आजकल 60 डिग्री उत्तर और 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैले प्रायः सभी क्षेत्रों में की जाती है।

■ गंगाशरण सैनी

देश में अनाजों के उत्पादन में तो काफी वृद्धि हुई है किंतु तिलहनों और दलहनों के उत्पादन में बहुत कम बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि विस्फोटक दर से हो रही है, जिसके कारण खाद्य तेलों की कमी और अधिक हो जाती है। अतः कृषि वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर जाना स्वाभाविक है। खाद्य तेल की आपूर्ति हेतु इनका विदेशों से प्रतिवर्ष आयात किया जाता है जिसके लिए हमें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। खाद्य तेलों की आपूर्ति और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सरसों वगीय फसलों को उगाना नितांत आवश्यक हो गया है। इसमें तोरिया एक ऐसी फसल है जो कम खर्च में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई है अतः वारानी क्षेत्रों में इसे उगाकर कृषक लाभ उठा सकते हैं।

जलवायु

तोरिया के सफल उत्पादन हेतु शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त मानी गयी है। इसे 20-40 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सुगमता से उगाया जा सकता है। भारत में इसे रबी मौसम में उगाया जाता है। इसकी खेती आजकल 60 डिग्री उत्तर और 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैले प्रायः सभी क्षेत्रों में की जाती है। अधिक खुला आसमान और पर्याप्त मृदा-आद्रता की आवश्यकता पड़ती है। पौधों में फूल आने और बीज निर्माण के समय बादल और कोहरे से भरे मौसम का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। भरपूर उपज के लिए सामान्यतः कम तापमान की आवश्यकता होती है। पाले से उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भूमि

वैसे तो तोरिया को हल्की एवं भारी मिट्टी में भलीभांति उगाया जा सकता है, परंतु इसके सफल उत्पादन के लिए उचित जल निकास वाली दोमट या भारी दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गयी है। तोरिया में लवणता सहन करने की विशेष क्षमता पायी गयी है। अतः इसे लवणीय मिट्टी में भी उगाया जा सकता है।

उन्नत किस्में ही उगाएं

तोरिया की अनेक उन्नत किस्में उपलब्ध हैं। अतः उन्नत किस्में ही उगानी चाहिए। तोरिया की प्रमुख किस्मों के चारित्रिक गुणों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है। किसानों को इन किस्मों में जो अच्छी लगे उसी का उगाना चाहिए।

टाइप-9: यह किस्म 90-95 दिन में तैयार हो जाती है। बीज से 40 प्रतिशत तेल निकलता है। प्रति हेक्टेयर 12-15 क्विंटल उपज मिल जाती है। सिंचित एवं असिंचित दोनों क्षेत्रों में उगाने के लिए उपयुक्त किस्म है। यह भूरे दाने वाली किस्म है।

टाइप-36: यह किस्म 100 दिन में तैयार हो जाती है। बीज से तेल 40 प्रतिशत मिल जाता है। प्रति हेक्टेयर 12-15 क्विंटल उपज मिल जाती है। यह पीले दाने वाली किस्म है। यह पंजाब और हरियाणा में उगाने के लिए उपयुक्त किस्म है।

संगम: यह किस्म 110 दिन में तैयार हो जाती है। बीज से 44.2 प्रतिशत तेल मिल जाता है। प्रति हेक्टेयर 12-15 क्विंटल उपज मिल जाती है। हरियाणा के सिंचित क्षेत्रों में उगाने के लिए उपयुक्त किस्म है।

टी.एल.-15: यह किस्म केवल 88 दिन में तैयार हो जाती है। बीज से 44 प्रतिशत तेल मिल जाता है। प्रति हेक्टेयर 8-10 क्विंटल उपज मिल जाती है। सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रों में उगाने के लिए उपयुक्त किस्म है।

आई.टी.एस.ए.: यह किस्म 105 दिन में तैयार हो जाती है। बीज से 44 प्रतिशत तेल मिल जाता है। प्रति हेक्टेयर 8-10 क्विंटल उपज मिल जाती है। इसके दाने भूरे रंग के होते हैं।

पंत तोरिया-303: यह किस्म 95 दिन में तैयार हो जाती है। बीज से 42 प्रतिशत तेल मिल जाता है। प्रति हेक्टेयर 15-20 क्विंटल उपज मिल जाती है। उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में उगाने के लिए उत्तम किस्म है।

पंत तोरिया-30: यह किस्म 95 दिन में तैयार हो जाती है। बीज से 42 प्रतिशत तेल मिल जाता है। बीज भूरे रंग के मध्यम आकार के होते हैं। यह मिश्रित खेती के लिए उपयुक्त किस्म है। प्रति हेक्टेयर 14-16 क्विंटल उपज देती है।

पंत तोरिया-505: यह किस्म 85-90 दिन में तैयार हो जाती है। बीज से 42 प्रतिशत तेल मिल जाता है। प्रति हेक्टयेर 14-16 क्विंटल उपज दे देती है। यह किस्म संपर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में उगाने के लिए उपयुक्त है।

भवानी (टी.के.-840): यह किस्म 75-85 दिनों में तैयार हो जाती है। बीज से 44 प्रतिशत तेल मिल जाता है। इस किस्म के पौधे 70-75 सेमी ऊंचे बढ़ते हैं। फलियां लंबी, बीज भूरे रंग के होते हैं। प्रति हेक्टेयर 12-15 क्विंटल उपज दे देती है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में उगाने के लिए उपयुक्त किस्म है।

टी.एच.-68: इस किस्म का विकास चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार लारा किया गया। यह किस्म 89 दिनों में तैयार हो जाती है। इसे उगाने के बाद गेहूं की बोआई की जा सकती है। प्रति हेक्टेयर 13-14 क्विंटल उपज दे देती है।

बी.आर.-23: यह किस्म 100 दिन में तैयार हो जाती है। बीज से 43 प्रतिशत तेल मिल जाता है। प्रति हेक्टेयर 8-10 क्विंटल उपज मिल जाती है। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में उगाने के लिए उपयुक्त किस्म है।

टी.एल.-15: यह किस्म 80-90 दिनों में तैयार हो जाती है। बीज से 44 प्रतिशत तेल मिल जाता है। प्रति हेक्टेयर 8-10 क्विंटल उपज मिल जाती है। पंजाब के सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी गयी है।

खेत की तैयारी

तोरिया की शुद्ध फसल लेने के लिए भूमि की तैयारी गेहूं की तरह की जानी चाहिए। फसल अच्छी तरह उगे और मजबूती से खड़ी रहे, इसके लिए खेत की मिट्टी बारीक एवं भुरभुरी कर लेनी चाहिए। इसके लिए 4-5 जुताइयों की आवश्यकता होती है। सभी जुताइयां सूर्य निकलने से पूर्व करें। ऐसा करने से खरपतवारों की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाती है। प्रत्येक जुताई के उपरांत पाटा अवश्य लगायें। भूमि में पर्याप्त नमी रहनी चाहिए ताकि बीजों का अंकुरण सुगमता से हो जाए।

बोआई

बोआई का समय: बोआई का समय क्षेत्र की जलवायु और फसल चक्र में तोरिया के स्थान पर निर्भर करता है। उत्तर भारत में तोरिया की बोआई सितंबर के प्रथम सप्ताह से सितंबर के अंतिम सप्ताह तक अवश्य कर देनी चाहिए। इसके उपरांत बोआई करने से उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तोरिया की फसल पर पाले का दुष्प्रभाव अधिक होता है, अतः सितंबर में बोना ही अच्छा रहता है।

बीज की मात्रा: तोरिया के बीज की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उसे अकेले उगाया जा रहा है या मिश्रित फसल के रूप में उगाया जा रहा है। विभिन्न परिस्थितियों में बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर निम्न प्रकार रखते हैं-

(1) अकेली पफसल - 4-6 किलो

(2) मिश्रित पफसल - 2-3 किलो

नोटः तराई क्षेत्रों में तोरिया की बीज दर 7-8 किलो तक रखी जा सकती है।

बीजोपचार: बीज प्रमाणित होना चाहिए। पफसल को फफूंदी जनित रोगों से बचाने के लिए थायरम (2.5 ग्राम रसायन प्रति किलो बीज) से उपचारित करना चाहिए।

बोआई की विधि: मिश्रित फसल अथवा अकेली फसल के रूप में तोरिया छिटकवां बोया जाता है, लेकिन पंक्तियों में शुद्ध फसल बोई जा सकती है। पंजाब और हरियाणा में किये गये समन्वित परीक्षणों से पता चला है कि तोरिया में पंक्ति और पौधे की आपसी दूरी क्रमशः 45-60 सेमी व 30 सेमी रखना ठीक रहता है।

खाद एवं उर्वरक

तोरिया थोड़े समय में अधिक वृद्धि करने वाली फसल है, अतः यह शीघ्रता से पोषक तत्व ग्रहण करती है। तोरिया की फसल को मृदा जांच के आधार पर खाद एवं उर्वरक देने चाहिए। साधारणतया 60-90 किलो नाइट्रोजन, 40-50 किलो फॉस्फोरस व 30-40 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा अमोनियम सल्फेट के रूप में देने से अच्छे परिणाम आते हैं, क्योंकि अमोनियम सल्फेट में 24 प्रतिशत गंधक पायी जाती है। फॉस्फोरस को सिंगल सुपर फॉस्फेट के रूप में देना चाहिए, क्योंकि इसमें 12 प्रतिशत गंधक पायी जाती है। पोटाश को पोटेशियम सल्फेट के रूप में देना चाहिए, क्योंकि इसमें 18 प्रतिशत गंधक पायी जाती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बोआई के समय देनी चाहिए और शेष आधी मात्रा बोने के 30-35 दिन बाद यूरिया के 3 प्रतिशत घोल के रूप में 2-3 बार छिड़काव लारा देने चाहिए। फॉस्फोरस का तेल वृद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सभी उर्वरक 2-3 सेमी गहरे सीड फटेड्रिल अथवा देशी हल से देने चाहिए। तोरिया के लिए सिंचित या

असिंचित क्षेत्रों में कितने उर्वरक दिये जाएं, इसे तालिका में स्पष्ट किया गया है। अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए 20 किलो कैल्सियम ऑक्साइड और 8-10 किलो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रति हेक्टेयर देना भी लाभप्रद पाया गया है। 5-10 टन गोबर की खाद भी प्रथम जोताई से पूर्व डालनी चाहिए।

सिंचाई

मिश्रित रूप में उगाई गयी फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता मुख्य फसल की अवस्था पर निर्भर करती है। तोरिया की शुद्ध फसल पंजाब में सिंचाई के आधार पर ही उगाते हैं। तराई वाली भूमि में जल स्तर ऊंचा होने के कारण सिंचाई नहीं की जाती है। कभी-कभी एक सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है। वैसे भूमि की किस्म और मौसम के अनुसार सिंचाई की जाती है। आम तौर पर दो सिंचाइयां देने से काम चल जाता है। भूमि में नमी बनी रहनी चाहिए। शुद्ध मौसम में तीन सिंचाइयां 25 दिन के अंतराल पर करनी पड़ सकती हैं।

खरपतवार नियंत्रण

तोरिया के साथ अनेक खरपतवार उग आते हैं जो पौधे के विकास एवं बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अतः उनकी रोकथाम के लिए आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करते रहें। एलाक्लोर, आइसोप्रोटोयूरान या नाइट्रोफेन की एक किलो मात्रा को 900 लीटर पानी में घोलकर फसल बोने के बाद और अंकुरण के पूर्व छिड़काव करने से खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है।

पौध संरक्षण

तोरिया की फसल को विभिन्न प्रकार के कीट एवं रोग उसकी विभिन्न अवस्थाओं में क्षति पहुंचाते हैं जिसके परिणामस्वरूप निम्न गुणवत्ता वाली कम उपज मिलती है। अतः आवश्यकतानुसार पौध संरक्षण उपाय अपनाने चाहिए ताकि उच्च गुणवत्ता वाली अधिक उपज मिल सके।

कीट

माहूः यह छोटा, कोमल शरीर वाला, हरे मटमैले भूरे रंग का होता है, जिसके झुंड पत्तियों, फूलों, डंठलों, फलियों आदि पर चिपके रहते हैं। ये कीट रस चूसकर पौधे को कमजोर कर देते हैं जिस कारण फलियों में दाने नहीं बनते। इस कीट का प्रकोप दिसंबर माह से प्रारंभ हो जाता है और बादल घिरे रहने पर इसका प्रकोप तीव्रता से होता है। इसकी रोकथाम हेतु अनेक कीटनाशी उत्तम पाये गये हैं। मैटासिस्टॉक्स (25 ईसी) एक लीटर, रोगोर (30 ईसी) एक लीटर या डाइमेक्रान (100 ईसी) 250 मिलीलीटर 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।

आरा मक्खीः इसकी सूंडियां काले रंग की होती हैं जो पत्तियों को बहुत तेजी से किनारों से या बीच में छेद कर खाती रहती हैं जिससे पत्तियां छलनी जैसी हो जाती हैं। इस कीट की रोकथाम हेतु मैलाथियान 5 प्रतिशत चूर्ण 20-25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें अथवा डेढ़ लीटर मैलाथियान 50 ईसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

रोग

झुलसाः यह एक फफंदी जनित रोग है। इसके कारण पौधे पीले पड़ जाते हैं और तेल की मात्रा घट जाती है। इसकी रोकथाम हेतु डाइथेन एम-45 का 0.20 प्रतिशत घोल का छिड़काव करना चाहिए। 15-20 दिन क अंतर पर 2-3 छिड़काव करने चाहिए।

मृदु रोमिल फफूंदः इसके कारण पत्तियों में सफेद चूर्ण सा दिखायी देता है और तेल की मात्रा घट जाती है। इसकी रोकथाम के लिए फसल पर ब्लाईटॉक्स 50 ईसी 0.1 प्रतिशत घोल का छिड़काव करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो 10-15 दिन के बाद दूसरा छिड़काव करें।

कटाई

तोरिया की विभिन्न किस्में 75-100 दिन में काटने योग्य हो जाती हैं। अतः तोरिया की फसल मध्य दिसंबर तक काटने योग्य हो जाती है। फसल पकने पर पौधे, पत्तियों व फलियों का रंग पीला पड़ने लगता है। अतः इस अवस्था में हंसिया से फसल की कटाई कर देनी चाहिए। 7-8 दिन सुखाकर डंडों के सहारे दाने अलग कर देने चाहिए।

उपज

तोरिया की उपज कई बातों पर निर्भर करती है जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति, तोरिया की किस्म व फसल की देखभाल प्रमुख हैं। यदि उपरोक्त विधि से तोरिया की खेती की जाए तो 12-15 क्विंटल बीज प्रति हेक्टयेर प्राप्त हो जाता है। ●

शर्मनाक है वैश्विक पोषण रिपोर्ट

वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2016 में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि किस प्रकार भारत कुपोषण से प्रभावी ढंग से निपटने में अभी तक पीछे है। कुपोषण वृद्धि रुकने, अपक्षय, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और वजन बढ़ने/मोटापे के रूप में परिलक्षित होता है। वृद्धि रुकने के संबंध में भारत 132 देशों में से 114वें स्थान (मामले 38.7%) पर है, जबकि अपक्षय के संबंध में 130 देशों में से 120वें स्थान (मामले 15.1%) पर है। गभर्धारण करने की आयु वाली महिलाओं के बीच एनीमिया प्रसार के बारे में भारत 185 देशों में से 170वें स्थान (मामले 48.1%) पर है। यह गंभीर चिंता का विषय है।

बीते वर्षों में सरकार ने जनता के बीच व्याप्त कुपोषण से निपटने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना 1975 में प्रारंभ की गयी थी। आईसीडीएस बच्चों की देखभाल और विकास के लिए दुनिया के विशालतम और सबसे अनोखे आउटरीच कार्यक्रमों में से एक है, जिसके अंतर्गत देश के सभी जिलों और प्रखंडों को शामिल किया गया है। इसी तरह मध्यान्न भोजन योजना को 1995 में सर्वव्यापी बनाया गया था। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल का अभाव है जो कुपोषण की अंतर-पीढ़ीगत और बहुमुखी प्रकृति से निपटने के लिए बेहद आवश्यक है।

इसी तरह, हालांकि वैश्विक स्तर पर यह अच्छी तरह से स्वीकार किया है कि पहले 1000 दिनों (गर्भाधान से 2 वर्ष प्रसवोत्तर) ध्यान केंद्रित करने से कुपोषण से निपटने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत में पोषण कार्यक्रम मुख्यतः जन्म के बाद की अवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अनुसंधानों से संकेत मिलता है कि दो साल की उम्र में विकास में होने वाली 50 प्रतिशत कमी मुख्य रूप से गर्भावस्था के दौरान और उससे पहले मां के खराब पोषण के कारण गर्भ में ही हो जाती है। इसलिए पर्याप्त पोषण की स्थिति (गर्भाधान से पूर्व और पहले तीन महीनों के दौरान जब ज्यादातर महिलाओं को अपनी गर्भावस्था के बारे में पता नहीं होता, भ्रूण के उचित विकास के लिए महत्वपूर्ण समय है। ●

प्लास्टिक लो टनल तकनीक

किसान प्लास्टिक लो टनल तकनीक से अगेती या बेमौसमी फसल उगाकर अधिक लाभ कमा सकते हैं क्योकि अगेती व बेमौसमी फसलों का बाजार भाव अधिक रहता है।

इस तकनीक द्वारा संरक्षित खेती का मुख्य उद्देश्य सब्जी फसलों को मुख्य जैविक या अजैविक कारकों से बचाकर उगाना होता है। इसमें फसल को किसी एक कारक या कई कारकों से बचाकर उगाया जा सकता है। संरक्षित सब्जी उत्पादन के लिए सब्जी उत्पादकों को संरक्षित खेती व विभिन्न संरक्षित संरचनाओं की पूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद ही उत्पादक तय कर सकता है कि वह किस प्रकार की संरक्षित तकनीक अपनाकर बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करे। कौन-कौन सी संरक्षित प्रौद्योगिकियां हैं जिनमें वह सब्जियों को वर्ष भर उगा सकता है। संरक्षित संरचनाओं को बनाने के बाद में रखरखाव में क्या व्यय होगा तथा उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों को वह किस बाजार में बेचकर अधिक लाभ कमा सकता है। इन सभी विषयों की जानकारी आवश्यक है।

मुख्यतः सब्जी उत्पादन हेतु उचित व उपयुक्त संरक्षित प्रौद्योगिकी की आवश्यकता उस क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करती है। लेकिन इसके अलावा किसान की आर्थिक दशा, टिकाऊ व उच्च बाजार की उपलब्धता व बिजली की आपूर्ति आदि कारक भी इसको निर्धारित करते हैं। सब्जियों के बेमौसमी उत्पादन हेतु मुख्यतः वातावरण अनुकूलित ग्रीनहाउस, प्राकृतिक वायु संचारित ग्रीनहाउस, कम लागत वाले पॉलीहाउस, वाक-इन-टनल, कीट अवरोधी नेटहाउस तथा लो प्लास्टिक टनल आदि संरचनाओं का उपयोग किया जाता है।

बेमौसमी सब्जियों की संरक्षित खेती के लिए सब्जियों की पौध प्लग ट्रे पद्धति से ग्रीनहाउस में तैयार की जाती है तथा उसके बाद पौधों को उपयुक्त संरक्षित संरचना में रोपाई करते हैं।

लो प्लास्टिक टनल तकनीक

लो प्लास्टिक टनल ऐसी संरक्षित संरचना है जिसे मुख्य खेत में फसल की रोपाई के बाद प्रत्येक फसल क्यारी के ऊपर कम ऊंचाई पर प्लास्टिक की चादर से ढककर बनाया जाता है। यह फसल को कम तापमान से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बनाई जाती है। यह तकनीक उत्तर भारत के उन मैदानों में सब्जियों की बेमौसमी खेती के लिए बहुत उपयोगी है जहां सर्दी के मौसम में रात का तापमान लगभग 40 से 60 दिनों तक 8 डिग्री सें.ग्रे. से नीचे रहता है।

इस तकनीक से बेमौसमी सब्जियां उगाने के लिए सब्जियों की पौध को प्लास्टिक प्लग ट्रे तकनीक से दिसम्बर व जनवरी माह में ही तैयार किया जाता है। ऐसी संरचना बनाने के लिए सबसे पहले ड्रिप सिंचाई की सुविधायुक्त उठी हुई क्यारियां उत्तर से दक्षिण दिशा में बनाई जाती हैं। इसके बाद क्यारियों के मध्य में एक ड्रिप लाइन बिछा दी जाती है। क्यारी के उपर 2 मिलीमीटर मोटे जंगरोधी लोहे के तारों या पतले व्यास के पाइपों को मोड़कर हुप्स या घेरे इस प्रकार बनाते हैं कि इसके दो सिरों की दूरी 50 से 60 सेमी तथा मध्य से ऊंचाई भी 50 से 60 सेमी रहे। तारों के बीच की दूरी 1.5 से 2 मीटर रखनी चाहिए। इसके बाद तैयार पौध को क्यारियों में रोपाई करते है तथा दोपहर बाद 20-30 माईक्रोन मोटाई तथा लगभग 2 मीटर चौड़ाई की पारदशी प्लास्टिक की चादर से ढका जाता है। ढकने के बाद प्लास्टिक के लम्बाई वाले दोनो सिरों को मिट्टी से दबा दिया जाता है। इस प्रकार रोपित फसल पर प्लास्टिक की एक लघु सुरंग बन जाती है।

यदि रात को तापमान लगातार 5 डिग्री सें.ग्रे. से कम है तो 7 से 10 दिन तक प्लास्टिक में छेद करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन उसके बाद प्लास्टिक में पूर्व दिशा की ओर चोटी से नीचे की ओर छोटे-छोटे छेद कर देते हैं। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है इन छेदों का आकार भी बढ़ाया जाता है। पहले छेद 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर बनाते हैं, बाद में इन्हे 1 मीटर की दूरी पर बना देते हैं। आवश्यकता अनुसार मौसम ठीक होने पर तापमान को ध्यान में रखते हुऐ टनल की प्लास्टिक को फरवरी के अंत से मार्च के प्रथम सप्ताह में पूरी तरह से हटा दिया जाता है। इस समय तक फसल काफी बढ़ चुकी होती है तथा कुछ फसलों में तो फलस्थापन भी आरम्भ हो चुका होता है। इस तकनीक से बेल वाली समस्त सब्जियों को मौसम से पहले या पूणर्तः बेमौसम में उगाना संभव है। विभिन्न बेल वाली सब्जियों में इस तकनीक से संभावित फसल अगेती इस प्रकार है-

चप्पन कद्दू - 40 से 60 दिन
लौकी - 30 से 40 दिन
करेला - 30 से 40 दिन
खीरा - 30 से 40 दिन
खरबूजा - 30 से 40 दिन

यह तकनीक उत्तर भारत के समस्त मैदानों तथा खासकर बड़े शहरों के आसपास सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। इस तकनीक को अपनाने से पूर्व किसानों को इन बेल वाली सब्जियों की पौध को भी संरक्षित क्षेत्र में ही तैयार करना होगा। यह तकनीक उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी लाभदायक है। इस प्रकार किसान प्लास्टिक लो टनल तकनीक से अगेती या बेमौसमी फसल उगाकर अधिक लाभ कमा सकते हैं क्योकि अगेती व बेमौसमी फसलों का बाजार भाव अधिक रहता है।

(साभारः kisanhelp.in)

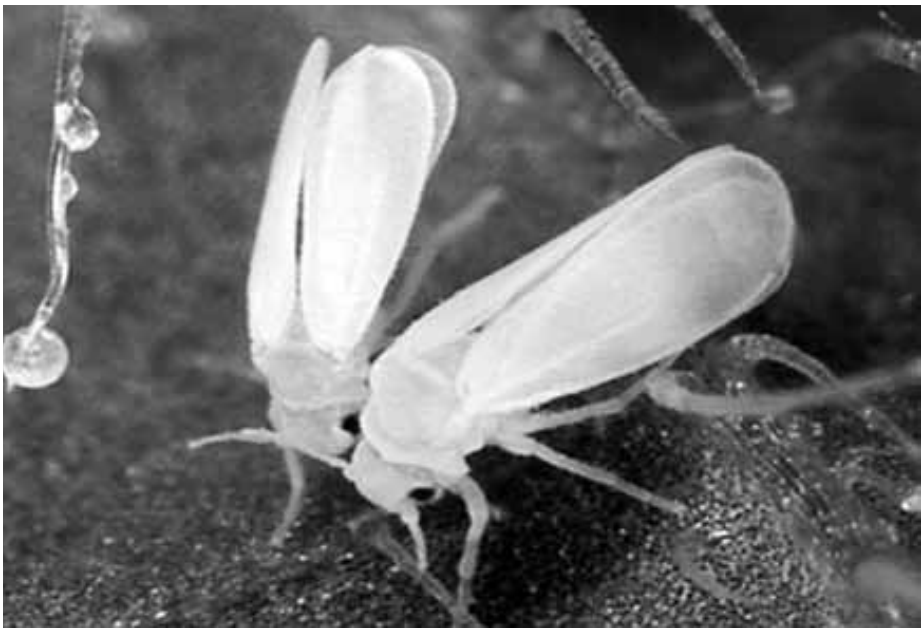

कपास की फसल पर सफेद मक्खी का कहर

पिछले वर्ष कपास की फसल की बर्बादी को देखते हुए इस बार पंजाब सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं जिनमें कॉटन एवं अन्य खरीफ फसलों के लिये 8 घंटे बिजली आपूर्ति, समय से फसल की बुआई एवं 25 लाख कॉटन के बीज के पैकेट (450 ग्राम प्रत्येक) की किसानों के लिये व्यवस्था करना इत्यादि।

■ **डॉ. एस. आर. सिंह**

पंजाब में मुख्य रूप से कपास की खेती भटिंडा, अबोहर, फजिल्का, मुक्तसर, फिरोजपुर एवं मानसा जिलों में की जाती हैं। पंजाब का यह कपास उत्पादक क्षेत्र मालवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है और कपास की फसल 'व्हाइट गोल्ड' के रूप में जानी जाती है, किन्तु पिछले वर्ष यह फसल किसान की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी और उनकी तबाही का कारण बनी।

पिछले वर्ष कपास की फसल की बर्बादी को देखते हुए इस बार पंजाब सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं जिनमें कॉटन एवं अन्य खरीफ फसलों के लिये 8 घंटे बिजली आपूर्ति, समय से फसल की बुआई एवं 25 लाख कॉटन के बीज के पैकेट (450 ग्राम प्रत्येक) की किसानों के लिये व्यवस्था करना इत्यादि। इस पैकेट की लागत 800 रुपए तय की गई।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना ने किसानों को सलाह दी है कि वे केवल चयनित 38 कॉटन प्रजातियों की ही बुवाई करें। इसके अलावा कृषि विभाग ने 500 स्काउट्स को भी इस कार्य पर नजर रखने के लिये लगाया है जो कि 24 घंटे कृषि प्रक्षेत्र एवं फसल पर नजर रखेंगे। इन सभी उपायों से इस वर्ष पंजाब में लगभग 25 प्रतिशत कॉटन का क्षेत्रफल बढ़ने की उम्मीद है।

पिछले वर्ष 2015 में पंजाब राज्य में एक हृदय विदारक घटना हुई जिसमें 15 किसानों एवं दो ट्रेडर्स बंधुओं ने आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाया। इस पूरी घटना ने न केवल पंजाब राज्य को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यह एक ऐसा संकेत था जिससे यह पता चल रहा था कि कहीं कुछ-न-कुछ गम्भीर रूप से गलत हो रहा है।

हमारे देश के कई हिस्सों में विभिन्न कारणों जैसे- फसल का उचित मूल्य न मिलना, फसलोत्पादन के लिये ऋण उपलब्ध न होना, समय पर ऋण का भुगतान न होना एवं अन्य कई कारणों से फसल खराब हो जाना आदि के कारण किसान आत्महत्या करते रहे हैं। किन्तु इस बार दो ट्रेडर्स बन्धुओं की आत्महत्या ने नीति-निर्माताओं के लिये एक नया संकेत दिया। इसकी गम्भीरता का पता इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उक्त आत्महत्याओं के बाद सम्पूर्ण पंजाब राज्य का सामाजिक ताना-बाना पटरी से लगभग उतर सा गया था।

आकलन करने पर पता चला कि इन आत्महत्याओं का मुख्य कारण कपास की फसल की बर्बादी को माना गया। यहां यह बताना आवश्यक है कि दोनों ट्रेडर बन्धु कीटनाशी दवाओं की दुकान चलाते थे। इस दुकान को चलाने के लिये उन्होंने कई जगह से ऋण ले रखा था और क्षेत्रीय किसानों को उधार में काफी कीटनाशी दवाईयां उपलब्ध कराई। किन्तु तभी सफेद मक्खी के तीव्र आक्रमण ने मालवा क्षेत्र की लगभग 60 प्रतिशत से अधिक फसल को अपनी चपेट में ले लिया। ये ट्रेडर बन्धु दोनों तरफ से वित्तीय दबाव में आ गए और अन्ततः उन्होंने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।

कपास के उत्पादन में पंजाब का 5वां स्थान है और यह फसल न केवल पंजाब की बल्कि भारत की भी एक मुख्य नगदी फसल है। कपास का उत्पादन विभिन्न राज्यों जैसे गुजरात (35 प्रतिशत), महाराष्ट्र (21 प्रतिशत), तेलंगाना एवं सीमान्ध्र (14 प्रतिशत), हरियाणा (8 प्रतिशत), पंजाब (7 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (6 प्रतिशत), राजस्थान (4 प्रतिशत), कर्नाटक (3 प्रतिशत) एवं अन्य (2 प्रतिशत) आदि में किया जाता है।

पिछले साल पंजाब में लगभग 11.25 लाख एकड़ कपास की फसल बोई गई जिसमें से लगभग 6.75 लाख एकड़ कपास की फसल सफेद मक्खी के आक्रमण से प्रभावित हुई। मालवा क्षेत्र के सिंघों गांव के एक किसान के अनुसार पंजाब के इस क्षेत्र में कॉटन की फसल को सफेद मक्खी से बचाने के लिये किसानों ने लगभग 10 से 12 बार कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल किया जिसकी लागत लगभग 3300 रुपए प्रति एकड़ प्रति बार आई। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी भी 4 एकड़ कपास की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गयी। किन्तु इसके बावजूद भी सफेद मक्खी का आक्रमण रोकने में कामयाबी नहीं मिली और इस तरह कीटनाशकों के इस्तेमाल पर लगभग 150 करोड़ रुपए व्यर्थ खर्च कर दिये गए।

प्रारंभिक अनुमान के आधार पर पंजाब के कृषि मंत्री ने कहा कि लगभग 20 से 25 प्रतिशत कपास की फसल सफेद मक्खी के आक्रमण से प्रभावित हुई है। किन्तु धीरे-धीरे इसका प्रभाव तेजी से फैलता गया, जिसके परिणामस्वरूप देखते-ही-देखते दो

महीने के अन्तर्गत लगभग दो तिहाई फसल खराब हो गई और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

अनुमान के मुताबिक सफेद मक्खी के आक्रमण से कपास की फसल को लगभग 4200 करोड़ रुपए की हानि हुई। हालांकि सफेद मक्खी का आना पंजाब में कपास की फसल के लिये कोई नई बात नहीं थी किन्तु इस बार वह इतनी तीव्र गति एवं संख्या में आई कि इससे पहले कोई कुछ समझ पाता सफेद मक्खी ने सम्पूर्ण फसल को अपनी चपेट में ले लिया।

अबोहर, फजिल्का, मानसा, भटिंडा एवं मुक्तसर जिलों में सफेद मक्खी का प्रकोप अधिक देखा गया। यहां तक कि कुछ क्षेत्रों में इसकी तीव्रता इतनी अधिक हो गई कि किसानों को अपनी खड़ी फसल को ट्रैक्टर से जोतना पड़ा या फसल को खेत से उखाड़ना पड़ा।

कपास की बर्बादी के कारण

1. किसानों को उपलब्ध कराए गए बीज उच्च गुणवत्ता युक्त नहीं थे। ये बीज काफी महंगे थे जिससे किसानों को फसल उगाने में ज्यादा लागत आई और इनका अंकुरण भी औसत ही रहा।
2. फसल पर छिड़के जाने वाले कीटनाशक के मदर कैमिकल को छोटी-छोटी फर्मों ने खरीद कर अपने स्तर पर उनमें मिलावट कर दुगुनी-तिगुनी मात्रा में पैकिंग कर किसानों को बेचा। अतः यह सफेद मक्खी पर प्रभावकारी नहीं रहे।
3. पछेती, खासतौर से 30 अप्रैल के बाद बोई गई फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप ज्यादा देखा गया क्योंकि पछेती फसल के पौधों का विकास उतना नहीं हो पाया था कि वे सफेद मक्खी के आक्रमण को सह पाते।
4. ज्यादातर किसानों ने बीटी कॉटन, जोकि विभिन्न कम्पनियों से ऊंचे दामों में खरीदी गई, की बुआई, की, उस पर सफेद मक्खी का प्रकोप देशी कॉटन की प्रजातियों के मुकाबले ज्यादा देखा गया।
5. वर्ष 2015 में अप्रैल-मई का तापक्रम अन्य वर्षों के मुकाबले कम होने से सफेद मक्खी पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और वह तेजी से भारी संख्या में फैलती गई।

सफेद मक्खी से बचाव के उपाय

1. फसल पर छिड़के जाने वाले कीटनाशक सरकार से लाइसेन्स धारक कम्पनी द्वारा निर्मित एवं पैक किये जाने के बाद ही बाजार में बिक्री के लिये उपलब्ध हों ताकि छोटी-छोटी फर्मों को मिलावट करने का मौका न मिले।
2. सरकार को नकली बीज एवं रसायनों की बिक्री को रोकने के लिये एक सघन निगरानी सेल बनाना चाहिए।
3. फसल की बुआई सही समय पर (15 से 30 अप्रैल) करनी चाहिए।
4. बीटी कॉटन के स्थान पर पंजाब सरकार द्वारा अनुशंसित प्रजातियों की बुआई की जाये क्योंकि प्रायः ऐसा देखा गया है कि देशी प्रजातियों पर सफेद मक्खी का प्रकोप कम पाया गया है।

-लेखक चौ. चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में उप निदेशक हैं

उत्तर पूर्वी राज्यों में जैविक खेती को प्रोत्साहन

भारत सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन परियोजना का शुभारंभ जनवरी 2016 को किया था। इस परियोजना के अर्न्तगत उत्तर पूर्व के सभी 8 राज्यों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन राज्यों की 50,000 हैक्टेयर भूमि को अगले तीन वर्षों में जैविक खेती में बदलना है। साथ ही कृषि मंत्रालय ने एक अन्य परियोजना परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) को भी पूरे भारतवर्ष में 2015 से क्रियान्वित किया है। इस परियोजना के अंतर्गत पूरे देश में अगले तीन वर्षों में 10,000 क्लस्टर का निर्माण कर दो लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल को जैविक खेती के रूप में विकसित करना है।

जैविक खेती के विभिन्न उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जायेगा। इसी क्रम में कृषि भवन, नई दिल्ली में दो स्टोर के माध्यम से विभिन्न जैविक उत्पादों को बेचे जाने की शुरूआत की गयी है। इन उत्पादों में उत्तर पूर्वी जैविक उत्पादों के साथ-साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों के जैविक उत्पादों की बिक्री भी की जायेगी। दूसरे स्टोर से जैविक कैफेटेरिया की सुविधा उपलब्ध की जायेगी जिससे सभी अधिकारियों एवं कमर्चारियों को दोपहर का खाना उपलब्ध होगा।

इस कार्य को करने के लिए सिमफेड (एसआईएमएफईडी) सिक्किम सरकार को अधिकृत किया गया है। यदि यह कार्य सफल रहा तो अगली योजना में इस प्रकार के स्टोर दिल्ली के अन्य परिसरों में भी खोले जायेंगे। योजना का उद्देश्य यह है कि देश के जैविक कृषकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके तथा समाज के अन्दर जैविक उत्पादों को बढ़ावा मिल सके। ●

गुलाब की व्यावसायिक खेती

■ कृषि चौपाल

प्राचीन काल से ही पूरी दुनिया में गुलाब की खेती की जाती है। इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में व्यावसायिक रूप से की जाती है। गुलाब के फूल डाली सहित या कट फ्लावर तथा पंखुड़ी फ्लावर दोनों तरह के बाजार में व्यापारिक रूप से पाये जाते हैं। गुलाब की खेती देशी तथा विदेशी बाजार दोनों ही रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। गुलाब को कट फ्लावर, गुलाब जल, गुलाब तेल, गुलकंद आदि के लिए उगाया जाता है। गुलाब की खेती मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अधिक की जाती है।

जलवायु और भूमि

गुलाब की खेती उत्तर एवं दक्षिण भारत के मैदानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में की जाती है। दिन का तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेट तथा रात का तापमान 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेट उत्तम माना जाता है। गुलाब की खेती हेतु दोमट मिट्टी तथा अधिक कार्बनिक पदार्थ वाली होनी चाहिए, जिसका पी.एच. मान 5.3 से 6.5 तक उपयुक्त माना जाता है।

प्रजातियां

गुलाब की लगभग 6 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। प्रथम संकर प्रजातियां जिसमें कि क्रिमसन ग्लोरी, मिस्टर लिंकन, लवजान, अफकैनेडी, जवाहर, प्रसिडेंट, राधाकृषणन, फर्स्ट लव, पूजा, सोनिया, गंगा, टाटा सैंटानरी, आर्किड, सुपर स्टार, अमेरिकन हेरिटेज आदि है। दूसरे प्रकार की पॉलीएन्था इसमें अंजनी, रश्मी, नर्तकी, प्रीत एवं स्वाती आदि। तीसरे प्रकार की फ्लोरीबण्डा जैसे कि बंजारन, देहली प्रिंसेज, डिम्पल, चन्द्रमा, सदाबहार, सोनोरा, नीलाम्बरी, करिश्मा सूर्यकिरण आदि। चौथे प्रकार की गैंडीफ्लोरा इसमें क्रींस, मांटेजुमा आदि। पांचवे प्रकार की मिनीयेचर ब्यूटी क्रिकेट, रेड फ्लस, पुसकला, बेबीगोल्ड स्टार, सिल्वर टिप्स आदि और अंत में छठवे प्रकार की लता गुलाब इसमें काक्लेट, ब्लैक बॉय, लैंड मार्क, पिंक मेराडोन, मेरीकलनील आदि पाई जाती हैं।

खेत की तैयारी

सुंदरता की दृष्टि से औपचारिक लेआउट करके खेत को क्यारियो में बांट लेते हैं। क्यारियों की लम्बाई-चौड़ाई 5 मीटर व 2 मीटर रखते हैं। दो क्यारियों के बीच में आधा मीटर स्थान छोड़ना चाहिए। क्यारियों को अप्रैल-मई में एक मीटर की गुड़ाई, एक मीटर की गहराई तक खोदकर 15 से 20 दिन तक खुला छोड़ देना चाहिए। क्यारियों में 30 सेंटीमीटर तक सूखी पत्तियों को डालकर खोदी गयी मिट्टी से क्यारियों को बंद कर देना चाहिए, साथ ही गोबर की सड़ी खाद एक महीने पहले क्यारी में डालना चाहिए। इसके बाद क्यारियों को पानी से भर देना चाहिए। साथ ही दीमक के बचाव के लिए फ्लीडाल पाउडर या कार्बोफ्यूरान 3 जी. का प्रयोग करेक लगभग 10 से 15 दिन बाद ओठ आने पर इन्ही क्यारियों में कतार बनाते हुए पौधे लगाने चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 30 गुणा 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। इस दूरी पर पौधे लगाने पर फूलों की डंडी लम्बी रहती है।

पौधशाला

जंगली गुलाब के ऊपर टी बडिंग द्वारा इसकी पौध तैयार होती है। जंगली गुलाब की कलम जून-जुलाई में क्यारियों में लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा दी जाती है। नवम्बर से दिसंबर तक इन कलमों में टहनियां निकल आती हैं। इन पर से कांटे चाकू से अलग कर दिए जाते हैं। जनवरी में अच्छे किस्म के गुलाब की टहनी जंगली गुलाब के ऊपर टी में लगाकर पॉलीथीन से कसकर बांध देते हैं। ज्यों-ज्यों तापमान बढ़ता है इनमें टहनी निकल आती है। जुलाई-अगस्त में रोपाई के लिए पौध तैयार हो जाती है।

पौधरोपण
पौधशाला से सावधानीपूर्वक पौध खोदकर सितम्बर-अक्टूबर तक उत्तर भारत में पौध की रोपाई करनी चाहिए। रोपाई करते समय ध्यान दें कि पिंडी से घास-फूस हटाकर भूमि की सतह से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर पौधों की रोपाई करनी चाहिए। पौध लगाने के बाद तुरंत सिंचाई कर देना चाहिए।

पोषण प्रबंधन
उत्तम कोटि के फूलों की पैदावार लेने के हेतु प्रूनिंग के बाद प्रति पौधा 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में मिलाकर सिंचाई करनी चाहिए। खाद देने के एक सप्ताह बाद जब नई कोपल फूटने लगे तो 200 ग्राम नीम की खली, 100 ग्राम हड्डी का चूरा तथा रासायनिक खाद का मिश्रण 50 ग्राम प्रति पौधा देना चाहिए। मिश्रण का अनुपात 1:2:1 मतलब यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटाश का होना चाहिए।

जल प्रबंधन
गुलाब के लिए सिंचाई का प्रबंधन उत्तम होना चाहिए। आवश्यकतानुसार गर्मी में 5 से 7 दिनों के बाद तथा सर्दी में 10 से 12 दिनों के बाद सिंचाई करते रहना चाहिए।

खरपतवार प्रबंधन
उत्तर प्रदेश के मैदानी भागो में कटाई-छंटाई हेतु अक्टूबर का दूसरा सप्ताह सर्वोत्तम होता है लेकिन उस समय वर्षा नहीं होनी चाहिए। पौधे में तीन से पांच मुख्य टहनियों को 30 से 40 सेंटीमीटर रखकर कटाई की जाती है। यह ध्यान रखना चाहिए कि जहां आंख हो वहां से 5 सेंटीमीटर ऊपर से कटाई करनी चाहिए। कटे हुए भाग को कवकनाशी दवाओं से जैसे कि कॉपर आक्सीक्लोराइड, कार्बेन्डाजिम, ब्रोडोमिश्रण या चौबटिया पेस्ट का लेप लगाना आवश्यक होता है।

रोग प्रबंधन
गुलाब में पाउडरी मिल्ड्यू या खर्रा रोग, उलटा सूखा रोग लगते हैं। खर्रा रोग को रोकने हेतु गंधक दो ग्राम प्रति लीटर पानी में या डायनोकॉप एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में या ट्राइकोडर्मा एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो छिड़काव दवा अदल-बदल कर करनी चाहिए। सूखा रोग की रोकथाम हेतु 50 प्रतिशत कॉपर आक्सीक्लोराइड को 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए जिससे सूखा रोग न लग सके।

कीट प्रबंधन
गुलाब में माहू, दीमक एवं सल्क कीट लगते हैं। माहू तथा सल्क कीट के दिखाई देने पर तुरंत डाई मिथोएट 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में या मोनोक्रोटोफास 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर 2-3 छिड़काव करना चाहिए। दीमक के नियंत्रण हेतु सिंचाई करनी चाहिए तथा फोरेट 10 जी. 3 से 4 ग्राम या फ्लीडाल 2 प्रतिशत 10 से 15 ग्राम प्रति पौधा गुड़ाई करके भूमि में अच्छी तरह मिला देना चाहिए।

फसल कटाई
सफ़ेद, लाल, गुलाबी रंग के फूलों की अधखुली पंखुड़ियों में जब ऊपर की पंखुड़ी नीचे की ओर मुड़ना शुरू हो जाये तब फूल काटना चाहिए। फूलों को काटते समय एक या दो पत्तियां टहनी पर छोड़ देना चाहिए जिससे पौधों की वहां से बढ़वार होने में कोई परेशानी न हो सके। फूलों की कटाई करते समय किसी बर्तन में पानी साथ में रखना चाहिए जिससे फूलों को काटकर तुरंत पानी में रखा जा सके। बर्तन में पानी कम से कम 10 सेंटीमीटर गहरा अवश्य होना चाहिए जिससे फूलों की डंडी पानी में डूबी रहे। पानी में प्रिजर्वेटिव भी मिलाते हैं। फूलों को कम से कम तीन घंटे पानी में रखने के बाद ग्रेडिंग के लिए निकालना चाहिए। यदि ग्रेडिंग देर से करनी हो तो फूलों को 1 से 3 डिग्रीसेंटीग्रेट तापक्रम पर कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहिए जिससे कि फूलों की गुणवत्ता बनी रहे।

पैदावार
गुलाब की उपज भूमि की उवर्रा शक्ति, फसल की देखरेख एवं प्रजातियों पर निर्भर करती है। फिर भी आमतौर पर लगभग 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। ●

खरीफ फसलों की बुवाई 1033 लाख हेक्टेयर

राज्यों से मिली रिपोर्टों के मुताबिक, 2 सितम्बर 2016 को कुल बुवाई क्षेत्र 1033.99 लाख हेक्टेयर आंका गया, जबकि पिछले साल इस समय यह आंकड़ा 997.11 लाख हेक्टेयर था।

यह जानकारी दी गई है कि 372.95 लाख हेक्टेयर में धान, 142.02 लाख हेक्टेयर में दलहन, 184.13 लाख हेक्टेयर में मोटे अनाज, 179.60 लाख हेक्टेयर में तिलहन, 45.77 लाख हेक्टेयर में गन्ना और 101.96 लाख हेक्टेयर में कपास की बुवाई/प्रतिरोपण हुआ है।

इस साल अब तक के बुवाई क्षेत्र (रकबा) और पिछले साल इस समय तक के बुवाई क्षेत्र का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

फसल	बुवाई क्षेत्र लाख हेक्टेयर
धान	372.95
दलहन	142.02
मोटे अनाज	184.13
तिलहन	179.60
गन्ना	45.77
जूट एवं मेस्ता	7.56
कपास	101.96
कुल	1033.11

NEW INDIA ASSOCIATES
OUR SERVICES
• Life Insurance/LIC Credit Card
• Car/Home Insurance
• Mediclaim
• Property Sale, Purchase & Renting at Delhi/NCR, Uttarakhand
LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
RELIANCE General Insurance
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
NARENDRA SINGH BISHT
S-557, Ist Floor, Hira Complex, School Block, Shakarpur, Delhi-110092
Ph: 9810369331, 9717494411, 011-22484945
E-mail: anjal2006@gmail.com

मुनाफे में एनटीपीसी

वित्त वर्ष 2016-17 की पहली तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनाटीपीसी का मुनाफा 5.65% बढ़कर 2369.53 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले कारोबारी साल की पहली तिमाही में कंपनी को 2242.79 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। इस समान अवधि में कंपनी की आमदनी 17,092.98 करोड़ रुपये से 11.52% बढ़कर 19,062.91 करोड़ हो गई है। कंपनी के बिजली उत्पादन में सालाना दस फीसदी की बढ़ोतरी हो रही है। एनटीपीसी की डिबेंचर्स और बांड के जरिए 15 हजार करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। कंपनी के नतीजों और आगे की योजनाओं पर बात करते हुए एनटीपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गुरुदीप सिंह ने बताया कि उनकी योजना वित्त वर्ष 2018 के अंत तक अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 60 हजार मेगावॉट करने की है। एनटीपीसी ने 2030 तक 1,28,000 मेगावॉट बिजली उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है।

ओएनजीसी को दीजिए नए विचार

उत्पादन कम होने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटने से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) का शुद्ध लाभ पहली तिमाही में 21 प्रतिशत घटकर 4,233 करोड़ रुपए रह गया, लेकिन इसके बावजूद कंपनी के हौसलों में कोई कमी नहीं आई है। कंपनी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में पदस्थ एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल हम घाटे में जरूर हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारी कंपनी जबरदस्त मुनाफे में होगी। शायद यही वजह होगी कि ओएनजीसी ने हाल ही में नए विचारों को मौका देने के लिए सौ करोड़ रुपए के एक स्टार्टअप की शुरूआत की है। ओएनजीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दिनेश के. सर्राफ ने बताया कि इस मुहिम का लक्ष्य देश के युवाओं को उद्यमी बनाने तथा तेल एवं गैस क्षेत्र से जुड़े नए विचारों को सामने लाना है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र ने देश के विकास में बहुत योगदान दिया है, लेकिन हालिया कुछ समय में इसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए तेल एवं गैस क्षेत्र को नए विचारों की जरूरत है। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि ओएनजीसी स्टार्टअप की शुरूआत केंद्र सरकार की महात्वाकांक्षी स्टार्टअप योजना के तहत की गई है। इसका लक्ष्य तेल एवं गैस क्षेत्र से संबंधित नए विचारों को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के लिए एक अलग वेबसाइट बनाई जाएगी।

महिलाओं के लिए पीएनबी की अनूठी पहल

देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक महिला केंद्रित कार्यक्रमों की पहल करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण में अहम जिम्मेदारी निभा रहा है। इस संबंध में पंजाब नेशनल बैंक की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक श्रीमती उषा अनंतसुब्रह्मण्यन ने बताया कि पंजाब नैशनल बैंक अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से विश्व की आधी आबादी अर्थात छात्राओं एवं महिलाओं को समर्थन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास कर रहा है और इस आबादी के लिए हम पीएनबी लाड़ली और महिला हेतु कौशल विकास कार्यक्रम लेकर आए हैं। बीते दिनों श्रीमती उषा अनंतसुब्रह्मण्यन ने राजस्थान के अलवर जिले के प्राचीन ऐतिहासिक शहर नीमराना में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आयोजित एक समारोह में कंप्यूटर प्रशिक्षुओं और महिला उद्यमियों को शिक्षा सामग्री, खेल की वस्तुओं, छात्रवृत्ति चेकों और प्रशंसा प्रमाण-पत्रों का वितरण किए। इस समारोह के दौरान 300 से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति भी वितरित की गई। यहां श्रीमती उषा अनंतसुब्रह्मण्यन ने कहा कि पीएनबी अपनी अनूठी पहलों और गतिविधियों के माध्यम से देश में वंचित वर्ग की आबादी के बीच अपनी पहुंच को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) को ऋण स्वीकृति पत्रों का वितरण भी इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण आकर्षण था। इस अवसर पर पीएनबी से अधिकारियों में डॉ. राकेश गुप्ता, श्री बीएम पाधा, श्रीमती कल्पना गुप्ता, श्री सुखमल जैन आदि उपस्थित थे।

पावरग्रिड को 33 प्रतिशत का मुनाफा

नवरत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को वित्त वर्ष 2016-17 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2016) में 1,819 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ है, जो कि 30 जून, 2015 को समाप्त समान तिमाही के दौरान दर्ज 1,343 करोड़ रुपये से 33 प्रतिशत अधिक है। पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2016) की कुल आय बढ़कर 6,259 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 4,793 करोड़ रुपये के मुकाबले 31 प्रतिशत अधिक है। पावर ग्रिड के प्रबंध निदेशक एल. एस. झा ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2016-17 के शुरूआती चार माह में पावर ग्रिड ने 10815 एमवीए की कुल परिवर्तन क्षमता वाले 2374 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइन और छह सब-स्टेशन को जोडा है। उन्होंने कहा कि पावर ग्रिड का निरीक्षण मानव रहित ड्रोन से किया जा रहा है और जिस जगह गड़बड़ी होने की आशंका होती है, उस जगह की फोटो ड्रोन से ली जाती है और बाद में गड़बड़ी को जल्द ही दुरुस्त कर दिया जाता है।

घाटे वाली एयर इंडिया को सात करोड़ की उम्मीद

लंबे से समय से कर्ज के बोझ तले दबी सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को पिछले वित्त वर्ष में सौ करोड़ रुपये का परिचालन मुनाफा होने की उम्मीद है, जबकि चालू वित्त वर्ष में उसका परिचालन लाभ सात करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद व्यक्त की गई है। दरअसल, एक ओर जहां वित्त वर्ष 2015-16 के आंकड़ों का अंकेक्षण को अंतिम रूप दिया जा रहा है, दूसरी ओर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि हमें विगत वित्त वर्ष में सौ करोड़ रुपये का परिचालन मुनाफा होने की पूरी उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण ईंधन

की कम कीमत के साथ कार्य-प्रदर्शन में सुधार होना है। चालू वित्त वर्ष की समाप्ति पर हमारा अनुमान है कि यह आंकड़ा बढ़कर 700-800 करोड़ रुपये हो जाएगा। लालकिले के प्राचीर से दिये अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम के कार्य प्रदर्शन में बदलाव के बारे में कहा था, आज मैं पूरे संतोष के साथ कह सकता हूं कि घाटे में चलने के लिए जानी जाने वाली एयर इंडिया ने अपने परिचालन में सुधार किया है, जिसके कारण उसे परिचालन मुनाफा होने जा रहा है।

HDFC BANK
We understand your world

एचडीएफसी के ग्राहकों को मिलेगा ऑनलाइन लोन

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने एसएमई कारोबारियों को लोन मुहैया कराने के लिए पहला डिजिटल एसएमई बैंक लांच किया है। अब छोटे एसएमई कारोबारियों को लोन लेने के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे। वे अपने ऑफिस में बैठे हुए वेबसाइट पर जरूरी कागजात अपलोड करके बैंक लोन के लिए आवेदन कर सकेंगे। बैंक उनको 24 घंटे में बता देगा कि उनको कर्ज मिल पाएगा या नहीं या उसे और कागजातों की जरूरत है। एचडीएफसी के बिजनेस बैंकिंग के प्रमुख असीम धू ने कहा कि इस सुविधा को शुरू करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि छोटे कारोबारी बैंक में लोन के लिए जाने में झिझक महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि बैंक में किससे मिलें, बैंक कौन-सा कागज मांगेगा, लोन मिलने में कितना समय लगेगा। यानी उनके लिए बैंक जाकर लोन लेना एक बड़ा चैलेंज है। हमारी वेबसाइट पर कोई भी एसएमई जाकर छह माह का बैंक स्टेटमेंट और प्रॉफिट-लॉस सर्टिफिकेट अपलोड कर सकता है। बैंक उसको 24 घंटे में बता देगा कि लोन मिलेगा या नहीं या किसी और डाक्युमेंट की जरूरत है। इसके अलावा इस सुविधा में पारदर्शिता होगी। एसएमई कारोबारियों को बैंक क्यूआर कोड देगा। एसएमई इस कोड के जरिए जान सकेगा कि उसके लोन एप्लीकेशन की स्टेटस क्या है।

सरकार के पास नहीं है बीमार पीएसयू का इलाज

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सात उपक्रमों को बंद करने की तैयारी कर ली है और इसके लिए जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी। इस प्रस्ताव पर संबंधित मंत्रालयों ने अपनी सहमति जता दी है। यह पहला मौका होगा, जब एक साथ इतने अधिक सार्वजनिक उपक्रम बंद करने की इजाजत मांगी जाएगी। जिन कंपनियों को बंद करने का प्रस्ताव है, वे घाटे में चल रहे 74 सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) की सूची में शामिल हैं। इनमें बर्ड जूट ऐंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेपर्स, हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स, टायर कॉरपोरेशन और रिचर्डसन एंड क्रूडास लिमिटेड शामिल हो सकती हैं। इससे पहले नीति आयोग ने सरकार और विनिवेश मंत्रालय को आठ पीएसयू की फेहरिस्त भेजी थी। वह इन्हें बंद कराना चाहता था, क्योंकि इन्हें पटरी पर नहीं लाया जा सकता था। लेकिन, शीर्ष सूत्रों ने बताया कि इनमें से एक पीएसयू की देखरेख करने वाले मंत्रालय ने इसे बंद करने से इनकार कर दिया और संकेत दिए कि उसे पटरी पर लाया जा सकता है, इसीलिए उसे सूची से बाहर कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि करीब सात बीमार पीएसयू को बंद किया जा सकता है। इन कंपनियों को पिछले तीन वर्षों से भारी घाटा हो रहा है। इन पीएसयू से जुड़े मंत्रालय अब इन्हें बंद करने के लिए विस्तृत योजना तैयार करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन कंपनियों में से कुछ पर काफी समय से चर्चा चल रही थी, लेकिन सभी के लिए मंत्रिमंडल से अलग-अलग मंजूरी लेने के बजाय एक ही बार में मंजूरी मांगी जाएगी। संबंधित मंत्रालय भी इस पर सहमत हैं कि इन कंपनियों में सुधार नहीं किया जा सकता और इसे बंद करने की जरूरत है।

पतंजलि

एएससीआई पर मुकदमा करेगी पतंजलि

पतंजलि आयुर्वेद ने भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) के खिलाफ मुकदमा दायर करने की धमकी दी है। एएससीआई ने योग गुरू रामदेव की इस कंपनी के खिलाफ इस वर्ष विज्ञापन नियमों के उल्लंघन के मामले में अब तक कुल 27 नोटिस जारी किए हैं। पतंजलि आयुर्वेद रोजमर्रा के उपयोग के सामान का कारोबार करती है। रामदेव ने कहा कि हम एएससीआई के खिलाफ मामला दायर करेंगे। यह मामला अदालत में बहुत जल्दी दायर किया जाएगा। हम इसकी संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और इस पर कार्रवाई जल्दी ही करेंगे। योगगुरू ने नियामक के नोटिसों को प्रेम-पत्र की संज्ञा दी, लेकिन जब उनसे उनके टूथपेस्टों की श्रंखला के प्रमाणन के बारे में पूछा गया तो वे चुप्पी साध गए। उनकी कंपनी यह पेस्ट दंत कांति ब्रांड नाम से बेचती है। रामदेव ने अधिकारियों और एएससीआई के रवैये पर सवाल खड़े किए और कहा कि एएससीआई को बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने खड़ा किया है और वे पतंजलि के विज्ञापनों के बारे में गलत संदेश फैला रहे हैं। वे हमें प्रेम-पत्र भेजते जा रहे हैं और यह मुद्दा संसद में भी उठ चुका है। एएससीआई ने पतंजलि के खिलाफ जिन शिकायतों को सही माना, उसमें पतंजलि के जीरा बिस्किट, कच्ची घानी सरसों तेल, केश कांति और दंत कांति जैसे उत्पादों के विज्ञापन शामिल हैं।

CAG
Comptroller and Auditor General of India

क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स का ऑडिट करेगा कैग

द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (सीएजी) सरकार की ओर से संचालित की जा रही फसल बीमा योजनाओं का ऑडिट करेगा। यह ऑडिट नौ राज्यों में किया जाएगा जिसमें, देखा जाएगा कि फसलों के बर्बाद होने के बाद ये योजनाएं किसानों को कितना राहत पहुंचा रही हैं। साथ ही इन योजनाओं का सही से किसानों को लाभ मिल भी रहा है या नहीं। सभी रिकार्ड दिखाएं बैंकःआरबीआई इस परफोर्मेंस ऑडिट में कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के रिकार्ड जांचे जाएंगे। इस ऑडिट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को भी निर्देश दिए हैं कि यदि ऑडिट में उनसे रिकार्ड मांगे जाते हैं तो वे सभी प्रॉपर रिकार्ड दिखाएं। क्योंकि, सभी स्कीम बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों और सहकारिता संस्थानों की मदद से ही संचालित की जा रही हैं। यह ऑडिट आंध्रप्रदेश, असोम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में किया. ऑडिट में इन राज्यों के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल और अकाउंटेंट जनरल (ऑडिट) भी साथ रहेंगे। फसल बर्बाद होने पर फ्रेश लोन दें बैंक आरबीआई ने बैंकों को एक और नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें फसल बर्बाद होने पर किसानों को फ्रेश लोन दिए जाने को कहा गया है। आरबीआई ने कहा कि यदि प्राकृतिक आपदा में किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है तो बैंकों को इंश्योरेंस क्लेम की रिसिप्ट का इंतेजार किए बगैर ही फ्रेश लोन दे दिया जाए। ●

हर चीज केंद्र को करनी है तो रावत वहां क्यों बैठे हैं?

हरिद्वार सीट से भाजपा के सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने उत्तराखंड में विकास न होने पर वतर्मान मुख्यमंत्री हरीश रावत को कटघरे में खड़ा किया। 'कृषि चौपाल' के साथ हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन कल्याणकारी योजनाओं को भाजपा सरकार ने शुरू किया था, हरीश रावत उन्हें भी जारी नहीं रख पाए। निशंक ने बताया कि वे जब मुख्यमंत्री बने थे, तब राज्य की माली हालत बहुत खराब थी, लेकिन केंद्र पर आरोप मढ़ने की बजाय उन्होंने सीमित संसाधनों में विकास की योजनाएं बनाईं, जिससे विकास सूची में उत्तराखंड दूसरे नंबर पर आ गया था। लेकिन आज स्थिति ठीक उलट है। इस मुद्दे पर उनसे लंबी बातचीत हुई।

● उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत दावा कर रहे हैं कि उन्होंने विकास की गंगा बहा दी है, जबकि आप कह रहे हैं कि राज्य में विकास कार्य ठप पड़ गए हैं?

उनके अलावा कोई और भी कह रहा है कि उत्तराखंड में विकास हो रहा है? सिर्फ अखबारी विकास हो रहा है। हर सरकार की अपनी स्थितियां-परिस्थितियां होती हैं और उसी से विकास की प्राथमिकताएं तय होती हैं। चादर छोटी हो तो पैर नहीं फैलाने चाहिए वरना नग्नता जाहिर हो जाती है, इसलिए जितनी चादर है उतने ही पांव पसारने चाहिए। हरीश रावत सरकार ने यही गलती की। उन्होंने राज्य को कंगाल कर दिया। अपने कमर्चारियों को तनख्वाह देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वे घोषणाओं पर घोषणाएं किए जा रहे हैं। पैसे के हिसाब से प्राथमिकताएं तय की जाती हैं। मैं जब मुख्यमंत्री था, तब समय पर राज्य के सभी कमर्चारियों को तनख्वाह मिल जाती थी और इससे संबंधित हर जिले की फाइल प्रत्येक महीने की दस तारीख को मेरी टेबल पर होती थी। 165 करोड़ रुपये के कर राजस्व को हम चार हजार करोड़ रुपये तक ले गए और विकास सूची में 70वें स्थान पर पड़े उत्तराखंड को हम दूसरे स्थान पर लाए, जबकि हरीश रावत उन योजनाओं को चालू तक नहीं रख पा रहे हैं, जो हमने शुरू की थीं। स्वास्थ्य के लिए हमने 108 एम्बुलेंस सेवा तो भोजन के लिए अटल खाद्य योजना शुरू की थी,

लेकिन हरीश रावत ने सारी योजनाओं का गला घोंट दिया। हम भी सत्ता में रहे, लेकिन हम चिल्लाते नहीं रहे। हमें मालूम था कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, उसे पूरा करने के लिए हमने 108 सेवा शुरू की, ताकि किसी व्यक्ति के प्राण न जाएं। 108 सेवा इतनी चर्चित हुई कि यह योजना एशिया में नंबर वन हो गई। हमने डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए 15 हजार रुपये में युवाओं को एमबीबीएस बनाने की योजना बनाई, क्योंकि हमें मालूम था कि लाखों रुपये खर्च करके डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले गांव-कस्बों की ओर नहीं जाएंगे, इसलिए हमने उन युवाओं को डॉक्टर बनाने की योजना बनाई, जो गरीब थे, लेकिन डॉक्टर बनना उनका सपना था। लेकिन इस सरकार ने फीस को बढ़ाकर फिर से लाखों कर दिया है। जब हरीश रावत चालू योजनाओं को ही जारी नहीं रख पाए, तो उनसे और क्या उम्मीद करें।

● हरीश रावत कह रहे हैं कि केंद्र उन्हें पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए राज्य के विकास कार्य रुके हुए हैं?

अगर हर चीज के लिए केंद्र को देना है, तो आप वहां क्यों बैठे हैं? हमने भी सरकार चलाई और तब केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन हमने ऐसा कोई अरोप नहीं लगाया। उस वक्त राज्य की पांचों सीटों पर कांग्रेस के सांसद थे, मैं पांचों सांसदों का हाथ पकड़कर उन्हें मनमोहन सिंह जी के पास ले गया। काम के लिए सबको साथ लेकर चला। हरीश रावत को समझना चाहिए कि भाषणबाजी और बयानबाजी से काम नहीं होते हैं।

● तो फिर रावत सरकार कहां असफल हुई, क्या वे नौकरशाही पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं?

वे गलत काम के लिए कहेंगे, तो अफसर उसे क्यों करेंगे? अगर मुख्यमंत्री में दम हो तो नौकरशाही की मना करने की हिम्मत ही नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री की ईमानदारी में दम होता है। जब अधिकारियों को गलत कामों के निर्देश मिलेंगे, तो वे उस पर कान ही नहीं देंगे वरना नौकरशाही से काम निकलवाना मुश्किल नहीं है। आप अधिकारी से तुरंत सवाल कीजिए कि मेरी चिट्ठी कहां रुकी? वह बताएगा कि वहां-वहां रुकी, तो आप गैर-जिम्मेदार अधिकारियों को घर बैठा दो। दो-चार अधिकारियों के साथ ऐसा होगा तो बाकी अपने आप सुधर जाएंगे। जब मैं मुख्यमंत्री था, तो मैं काम सौंपने से पहले अधिकारी से पूछता था कि क्या आप इसे कर पाएंगे या फिर मैं किसी और को ये जिम्मेदारी दूं? अधिकारी ना कह ही नहीं पाते थे, तब उन्हें मन मारकर ही सही समय पर काम करना पड़ता था। तब योजना आयोग ने एक चार्ट बनाया था, जिसमें उत्तराखंड वित्तीय, कृषि, सर्विस हर क्षेत्र में बहुत आगे था और आज तक राज्य का कोई मुख्यमंत्री उसे छू तक नहीं पाया।

● रावत सरकार ने नए जिलों की घोषणा की है, क्या इसमें भी उनकी कोई राजनीति छिपी है?

मैंने हरीश रावत से पूछा कि मेरे मुख्यमंत्री काल में जिन चार जिलों की घोषणा हुई थी, उन्होंने अब तक वहां डीएम क्यों नहीं बैठाए, जबकि इन जिलों पर शासनादेश तक जारी हो गया था, केवल अधिसूचना भर होनी थी। उन्होंने उन चार जिलों को तो नहीं बनाया, बल्कि उन्हें डर सता रहा है कि वे दोबारा नहीं आ पाएंगे, इसलिए लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ और जिलों की घोषणा कर दी।

● लेकिन आपके बाद आपकी पार्टी के भुवन चंद्र खंडूरी मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने भी ये जिले नहीं बनाए?

इन जिलों के सीमांत में रहने वाले लोगों का इस बात पर विवाद था कि हम फलां जिले में रहेंगे। इसी को समझने के लिए कमेटी बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी थी, इसलिए खंडूरी जी को भी समय नहीं मिल पाया था।

● आदर्श गांव योजना प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, आपके गोद लिए गांव की क्या स्थिति है और आप दूसरा गांव कब गोद ले रहे हैं?

मैंने गोवर्धनपुर गांव को गोद लिया, जो उत्तराखंड और उत्तर भारत में पहले और देश में 7वें नंबर पर है। अभी वहां के लिए 25 करोड़ रुपये की एक और योजना आने वाली है, उसके बाद गोवर्धनपुर और उभरेगा। इस धन से वहां एक फुली ऑटोमेटिक गोशाला का निर्माण किया जाएगा जिसमें एक हजार गाएं होंगी। मैं गोवर्धनपुर को फिर से गोवर्धनपुर बनाने में जुटा हुआ हूं। सब्जियों के बाद अब वहां के लोग दूध भी बाहर भेजेंगें। इससे उन्हें भरपूर रोजगार और आजीविका प्राप्त होगी। ग्रामवासी खुशहाल और उन्नत होंगे। जहां तक दूसरे गांव को गोद लेने की बात है तो उसका भी चयन कर लिया गया है, लेकिन उसकी घोषणा बाद में करूंगा। ●

'कृषि चौपाल' पत्रिका डाक से मंगाने के लिए सदस्यता फॉर्म

● **एक वर्ष (12 अंक) : रु. 200** ● **दो वर्ष (24 अंक) : रु. 380** ● **पांच वर्ष (60 अंक) : रु. 950**

सदस्य का नाम .....

डाक का पता .....

..... राज्य ..... पिन कोड .....

फोन/मोबाइल ..... ई-मेल .....

चेक/डिमांड ड्राफ्ट संख्या ..... रुपये ..... बैंक व ब्रांच का नाम .....

दिनांक ..... हस्ताक्षर .....

-: कृपया ध्यान दें :-

पत्रिका भारतीय डाक विभाग की पोस्टल सेवा से भेजी जाएगी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट '**KRISHI CHAUPAL**' के नाम देय होगा। उसके पीछे अपना नाम, पता एवं फोन नंबर लिखकर नीचे दिये गये पते पर भेजें:-

कृषि चौपाल, सी-355, तृतीय तल, गली नं.-9, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092, फोन: +91-991040-6059

किसानों का आयात

लड़के ने कहा – 'हमारे पापा ने तो साहूकार से कर्ज लिया था। उनके मर जाने के बाद साहूकार कुछ दिन तक तो चुप रहा। अब अक्सर आ धमकता है और कहता है कि कर्ज चुकाए बगैर तुम्हारे पिताजी को परलोक में मुक्ति नहीं मिलेगी। मम्मी सोच रही है कि जमीन बेच कर इस बला से किसी तरह छुटकारा पाएं।'

■ राजकिशोर

केन्द्रीय बजट में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा सुन कर नेताजी की आंखों में आंसू आ गए। आसमान की ओर दोनों बांहें उठा कर उन्होंने आंखे मूंद लीं और कहा - 'प्रभु, तुम सचमुच दयालु हो। तुमने आखिर मेरी सुन ली। अब मैं कम से कम अपने चुनाव क्षेत्र में मुंह तो दिखा सकूंगा।'

संसद की बैठक अभी चल रही थी, पर नेताजी अगले दिन की पहली ट्रेन से अपने चुनाव क्षेत्र में पहुंच गए। जब से उनके इलाके में किसान आत्महत्या करने लगे थे, नेताजी ने अपने चुनाव क्षेत्र में पैर नहीं रखा था। वे लगातार दिल्ली में ही बने रहे। किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के बारे में पहले तो उन्होंने बयान दिया कि यह सब विरोधियों का दुष्प्रचार है। जब इससे काम नहीं चला, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि ये आत्महत्या के मामले नहीं हैं, किसानों ने आपसी रंजिश से एक-दूसरे की जान ली है। जब यह भी नहीं जमा, तो नेताजी ने फरमाया कि आत्महत्या की घटनाएं दुनिया भर में बढ़ रही हैं - वास्तव में यह किसी विशेष क्षेत्र की नहीं, आतंकवाद की तरह ही एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए इसका समाधान विश्व स्तर पर ही हो सकता है। बाद में उन्होंने इस विषय पर बोलना ही छोड़ दिया। जब कोई पत्रकार जिद करने लगता, तो वे बिफर जाते - 'लगता है, आप अखबार नहीं पढ़ते! इस विषय में क्या हमारी पार्टी के किसी नेता ने बयान दिया है? फिर आप मेरा मुंह क्यों खुलवाना चाहते हैं? जब इस बारे में पार्टी कोई निर्णय लेगी, तब आपको प्रेस स्टेटमेंट मिल जाएगा।'

नेताजी जिस गांव में सबसे पहले पहुंचे, वहां उनके दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ आई। माला लेकर खड़े लोगों से उन्होंने कहा, मैं यहां अपना स्वागत करवाने नहीं, किसान भाइयों की पीड़ा में शिरकत करने आया हूं। उन्हें यह बताने आया हूं कि किसानों को राहत देने के लिए हमारी सरकार ने कितना क्रांतिकारी कदम उठाया है। पहले मुझे उस परिवार में ले चलिए, जहां किसी किसान ने आत्महत्या की हो।

पीड़ित परिवार के घर तक पहुंचते-पहुंचते नेताजी का चेहरा रुआंसा हो चुका था। परिवार में मृत किसान की पत्नी और तीन बच्चे थे। उन्होंने नेताजी को खाट पर बैठाया और तश्तरी पर गुड़ तथा गिलास में पानी लेकर उनके सामने हाजिर हो गए। नेताजी ने किसान की पत्नी से कहा - 'बहन, जो होना था, वह हो गया। होनी को कौन टाल सकता है! अब चिन्ता की कोई बात नहीं है। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि सभी किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा।' बहन कुछ नहीं बोली। मन ही मन सिसकती रही। उसके बड़े लड़के ने, जो दसवीं में पढ़ता था, जवाब दिया - 'लेकिन सर, अखबार में छपा है कि उन्हीं किसानों के कर्ज माफ होंगे, जिन्होंने बैंक से लोन लिया था।' नेताजी ने पुष्टि की - 'हां बेटा, तुमने ठीक सुना है। तुम्हारे परिवार पर कितना कर्ज है?' लड़के ने कहा - 'हमारे पापा ने तो साहूकार से कर्ज लिया था। उनके मर जाने के बाद साहूकार कुछ दिन तक तो चुप रहा। अब अक्सर आ धमकता है और कहता है कि कर्ज चुकाए बगैर तुम्हारे पिताजी को परलोक में मुक्ति नहीं मिलेगी। मम्मी सोच रही है कि जमीन बेच कर इस बला से किसी तरह छुटकारा पाएं।' नेताजी ने ढाढस बढ़ाया - 'न-न, जमीन कभी मत बेचना। जिन्होंने साहूकारों से कर्ज लिया है, उन्हें राहत देने के बारे में भी हम सोच रहे हैं।'

अब नेताजी वहां से जल्द से जल्द खिसकने की सोचने लगे। उनके चेहरे पर निराशा साफ-साफ झलक रही थी - यहां आना बेकार रहा। उसके बाद वे दूसरे गांव में गए। लेकिन वहां भी समस्या थी। पता चला कि जिस किसान ने आत्महत्या की थी, उसके घरवाले बैंक के तगादों से परेशान होकर गांव छोड़ कर चले गए हैं। कहां गए, यह पूछने पर जवाब मिला - 'पता नहीं। शहर में कहीं मजदूरी कर रहे होंगे। इस साल तो उनकी जमीन की बुआई भी नहीं हुई।' अन्त में तीसरे गांव में सफलता मिली। वहां कई लोगों ने बैंक से कर्ज ले रखा था। उन्होंने नेताजी का जबरदस्त स्वागत किया। जब नेताजी उठने लगे, तब एक बूढ़े किसान ने उन्हें रोक लिया। कहा, 'आपने हर्षवर्धन का नाम सुना होगा।' नेताजी का भावहीन चेहरा देख कर वह बोला- 'हर्षवर्धन उज्जैन का राजा था। कहते हैं, कुंभ के अवसर पर वह अपना सब कुछ दान कर देता था - यहां तक कि अपने पहने हुए कपड़े भी। अपनी बहन से मांग कर कपड़े पहन लेता। लेकिन अगले कुंभ तक उसके पास सब कुछ पहले जैसा ही जमा हो जाता था। वह फिर सब कुछ दान कर देता। हम किसानों का हाल वैसा ही है। इस बार कर्ज माफी हो गई है। पांच साल बाद हम फिर कर्ज से लद जाएंगे। सरकार कितनी दफा कर्ज माफी करेगी? इससे बेहतर क्या यह नहीं होगा कि आप लोग खेती के बारे में अपनी नीतियां ही बदल दें, ताकि किसानों पर न कर्ज लदे, न उसे माफ करने की जरूरत पड़े?'

बताते हैं, उस रात नेताजी को ठीक से नींद नहीं आई। वे सपने में बड़बड़ा रहे थे - इस देश के किसान ही गड़बड़ हैं। लगता है, हमें अन्न के साथ-साथ किसानों का भी आयात करना होगा। ●

आवश्यक सूचना

'कृषि चौपाल' पत्रिका को देश के हर जिले में लेखकों एवं विज्ञापन प्रतिनिधियों की आवश्यकता है। कृपया नीचे दिये गये मोबाइल नंबर एवं ईमेल पर संपर्क करें:-

+91-9910406059

krishichaupal@gmail.com

ACME ENTERPRISES®

(A unit of AEMPL)

Established in the year 1990, Acme Enterprises (A Unit of AEMPL) is a well managed an ISO 9001-2008, EN ISO 13485-2003, EMS 14001-2004, CE Certified Company, manufacturer, supplier, wholesaler, and exporter of the complimentary range of Hospital Furniture. Our product array also includes Hospital Beds, Delivery Tables, Ward Furniture and Patient Transfer Trolley. With these products, we also provide quality services to our clients such as facility management services. By providing all these remarkable services helps us to attain the level of a supreme grade service provider. Besides this, a significant number of products are exported to the foreign countries in a quick & fast manner. Our exclusive product range is famous for its features in the national as well as international countries.

Service with a professional touch.....

SCO : Kh. No. 295/2, Near Palam Vihar More, Main Road Bijwasan, New Delhi-110061 (India)
Phone: 011-28061086 Email: hospital-furniture@aempl.in Website: www.acmehospitalfurniture.co.in

Works: F-9, RIICO Industrial Area, Road No. 2, Hirawala, Kanota, Jaipur-303012 (Rajasthan)
Phone: +91-1429-234155

RNI Regd. No. DELHIN/2007/20953 Postal Regd No.: DL(E)-20/5505/2016-18

MADE EASY

India's Best Institute for IES, GATE & PSUs

Crack in 1st Attempt

ESE, GATE & PSUs

• Best Faculty • Best Study Material • Best Results

Why most of the students prefer MADE EASY!

Comprehensive Coverage
- More than 1000 teaching hours
- Freshers can easily understand
- Emphasis on fundamental concepts
- Basic level to advance level
- Coverage of whole syllabus (Technical and Non technical)

Focused and Comprehensive Study Books
- Thoroughly revised and updated
- Focused and relevant to exam
- Comprehensive so that, there is no need of any other text book
- Designed by experienced & qualified R&D team of MADE EASY

Dedication and Commitment
- Professionally managed
- No cancellation of classes
- Pre-planned class schedule
- Starting and completion of classes on time
- Subjects completion in continuity
- Co-operation and discipline

Complete guidance for written and personality test
MADE EASY has a dedicated team which provides round the year support for
- Interpersonal Skills
- GD and Psychometric Skills
- Communication Skills
- Mock Interviews

Motivation & Inspiration
- Motivational Sessions by experts
- Expert Guidance support
- Interaction with ESE & GATE toppers

Regular updation on Vacancies/Notifications
- Display on notice board and announcement in classroom for vacancies notified by government departments
- Notification of ESE, GATE, PSUs and state services exams

Professionally Managed & Structured Organization
- MADE EASY has pool of well qualified, experienced and trained management staff

Best Pool of Faculty
- India's best brain pool
- Full time and permanent
- Regular brain storming sessions and training
- Combination of senior professors and young energetic top rankers of ESE & GATE

Consistent, Focused and Well planned course curriculum
- Course planning and design directly under our CMD
- GATE & ESE both syllabus thoroughly covered
- Course coordination and execution directly monitored by our CMD

Best Infrastructure & Support
- Well equipped audio-visual classrooms
- Clean and inspiring environment
- In campus facility of photocopy, bookshop and canteen
- Best quality teaching tools

Regular Assessment of Performance
- Self assessment tests (SAT)
- ESE all India Classroom Test Series
- GATE Online Test Series
- Subject-wise classroom tests with discussion
- Examination environment exactly similar to GATE & UPSC exams

Counseling Seminars and Guidance
- Career counseling
- Post GATE counseling for M.Tech admissions
- Techniques for efficient learning
- Full Time Interview support for IES & PSUs

Timely completion of syllabus
- 4-6 hrs classes per day
- Well designed course curriculum
- Syllabus completion much before the examination date

Maximum Selections with Top Rankers
- MADE EASY is the only institute which has consistently produced Toppers in IES, GATE & PSUs
- Largest Selections in GATE
- Largest Selections in IES

Audio Visual Teaching | Hostel Support | Safe, Secured and Hygienic Campus Environment

Courses offered at MADE EASY

- Regular/Weekend/Super Talent Batches
- Rank Improvement Batches
- Online Test Series
- Postal Study Course
- MADE EASY Books
- Interview Guidance Program

Selections from MADE EASY in GATE 2016 & ESE 2015

MADE EASY Students Top in ESE-2015 | 38 Selections in Top 10 | 351 Selections out of total 434 | MADE EASY selections in ESE-2015 82% of Total Vacancies

MADE EASY Students Top in GATE-2016 | 53 Selections in Top 10 | 368 Selections in Top 100 | 1st Rankers in 6 Streams ME • EE • EC • IN • CS • PI

Streams: CE ME EE EC CS IN PI

For more details, visit : www.madeeasy.in

Delhi	Noida	Lucknow	Jaipur	Bhopal	Indore	Pune	Hyderabad	Bhubaneswar	Kolkata	Patna
011-45124612	0120-6524612	09919111168	0141-4024612	0755-4004612	0731-4029612	020-26058612	040-66774612	0674-6999888	033-68888880	0612-2356615
09958995830	08860378009	08400029422	09166811228	08120035652	07566669612	09168884343	040-24652324	09040999888	08282888880	09955991166

Corporate Office: 44-A/1, Kalu Sarai (Near Hauz Khas Metro Station) New Delhi-110016; Ph: 011-45124612